

My Notes.....

राष्ट्रीय

देश का पहला मानवरहित टैंक

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने मानवरहित, दूर से संचालित टैंक 'मंत्रा' विकसित किया है। मानवरहित टैंक 'मंत्रा' के तीन प्रकार हैं- निगरानी (सर्वाइलेंस), माइन ब्लास्ट और परमाणु और जैव खतरे वाले क्षेत्रों में पुनर्निर्माण। अवाडी में काम्बैट वेहिकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैबलिशमेंट (सीवीआरडीई) द्वारा आर्मी के लिए विकसित इस टैंक का परक्षण किया गया। जिसपर पैरामिलिट्री ने नक्सल ग्रस्त इलाके में इसके उपयोग में रुचि दिखाई है। जिसके लिए कुछ संशोधनों की आवश्यकता होगी। अवाडी में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देते हुए डीआरडीओ ने एक एकजीबिशन 'साइंस फॉर सोलजर्स' का आयोजन किया जिसमें आर्मर्ड टैंक की तरह दूर से ऑपरेट किए जाने वाले टैंकों को डिस्प्ले में रखा गया।

क्या है

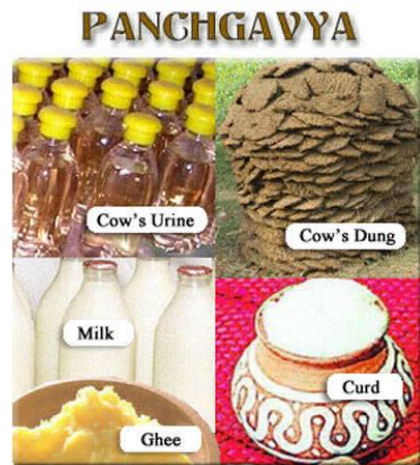
1. मंत्रा-एस देश का पहला मानवरहित ग्राउंड व्हिकल है जो निगरानी के मिशन के लिए है जबकि मंत्रा-एम माइन का पता लगाने के लिए और मंत्रा-एन उन जगहों के लिए है जहां न्यूक्लियर रेडिएशन या बायो वेपन का खतरा होगा। इसमें सर्वाइलेंस रडार, लेजर रेंज फाइंडर के साथ एक कैमरा जो दुश्मन का पता लगाकर 15 किमी की दूरी से हमला कर सकता है।
2. डीआरडीओ के चेयरमैन एस क्रिस्टोफर ने कहा कि डिस्प्ले किए गए प्रोडक्ट से संस्थान की क्षमता का प्रदर्शन किया गया है। क्रिस्टोफर ने कहा डीआरडीओ एक या दो वेपन सिस्टम का निर्यात करना चाहती है, जो सेना के लिए बेमानी हो गए हैं क्योंकि उन्होंने नए संस्करणों को हासिल कर लिया है।
3. पुराने वर्जन कुछ देशों के लिए अच्छे हैं। विकास के तहत भी कुछ सिस्टम हैं जिनका निर्यात किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि डीआरडीओ उत्पाद दुनिया में अच्छे माने जाते थे।
4. दुनिया में हम लड़ाकू विमानों के क्रम में चौथे, मिसाइलों के लिए पांचवें स्तर पर हैं। उन्होंने बताया, 'यदि हम पांच सालों में 5 लाख करोड़ रुपये अर्जित कर लेते हैं तब हमें फंड के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहना होगा।

गाय से फायदे पर शोध के लिए समिति

केंद्र सरकार ने गाय से मिलने वाले फायदे के वैज्ञानिक आधार पर शोध के लिए 19 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसमें और तीन सदस्य शामिल हैं। अंतर विभागीय सर्कुलर और समिति के सदस्यों से इस बारे में जानकारी मिली है।

क्या है

1. समिति पंचगव्य यानी गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध, दही और घी के पोषण, स्वास्थ्य और कृषि समेत विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले फायदे को वैज्ञानिक तौर पर साबित करने के लिए प्रोजेक्ट का चयन करेगी।
2. समिति का नाम संचालन समिति रखा गया है। विज्ञान और तकनीक मंत्री हर्षवर्धन इसके प्रमुख बनाए गए हैं। इसके अलावा समिति में विज्ञान एवं तकनीक विभाग, बायोटेक्नोलॉजी, नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिवों, आइआइटी-दिल्ली के वैज्ञानिकों को सदस्य बनाया गया है।
3. आरएसएस और विहिप से जुड़े विज्ञान भारती और



गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र के तीन सदस्यों को भी समिति में शामिल किया गया है। विज्ञान भारती के अध्यक्ष विजय भाटकर को समिति का सह अध्यक्ष बनाया गया है।

4. भाटकर परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। सीएसआइआर के पूर्व निदेशक आरए माशेलकर को भी समिति का सदस्य बनाया गया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब देश में गोरक्षकों द्वारा मवेशी व्यापारियों और सदिग्ध गाय तस्करों से मारपीट की घटना बढ़ी है।
5. सरकार ने इस परियोजना का नाम स्वरोप यानी साइंटिफिक वैलिडेशन एंड रिसर्च ऑन पंचगव्य (एसवीएआरओपी) रखा है। इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम बताया है।
6. इस कार्यक्रम में अन्य संबंधित मंत्रालयों, सरकारी विभागों, अकादमिक संस्थानों, शोध प्रयोगशालाओं, स्वयंसेवी संगठनों और अन्य की भी भागीदारी होगी।

पहली बार प्राइवेट सेक्टर ने बनाए युद्धपोत

देश में पहली बार नेवी के लिए प्राइवेट सेक्टर के शिपयार्ड में बने दो युद्धपोत पानी में उतारे गए हैं। नेवी के वाइस एडमिरल गिरीश लूथरा ने इस लॉन्च को मील का पत्थर बताया है। अभी तक सरकारी शिपयार्डों में ही युद्धपोतों के स्वदेशीकरण का काम चल रहा था।

क्या है

1. रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने 25 जुलाई को गुजरात के पीपावाव में नेवी के लिए दो ऑफशोर पेट्रोल वेसेल (OPV) लॉन्च किए, जिनके नाम शचि और श्रुति हैं।
2. नेवी के लिए पी-21 प्रोजेक्ट के तहत 5 OPV बनाए जा रहे हैं। इनका काम देश की विशाल समुद्री सीमा की रक्षा करना है। समुद्री डकैती रोकने के लिए होने वाली गश्ती में इनका रोल अहम समझा जाता है।
3. इन युद्धपोतों में 76 mm का सुपर रैपिड गन माउंट सिस्टम लगा है। साथ में 30 mm की दो AK-630M गन हैं।
4. इनसे मीडियम और शॉर्ट रेंज की रक्षा क्षमता मिलेगी। इन हथियारों को रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सकता है।
5. शिप का पूरा ऑपरेशन इंटेलिजेंट इंटीग्रेटेड प्लेटफार्म मैनेजमेंट सिस्टम से चलाया जाता है।

आंशिक रूप से हासिल हुआ है मिलेनियम विकास लक्ष्य 2015

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत मिलेनियम विकास लक्ष्य 2015 आंशिक रूप से ही हासिल हो पाया है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शिशु मृत्यु दर (आइएमआर) और मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में कमी लाने का लक्ष्य देशव्यापी स्तर पर पूरी तरह से नहीं साधा जा सका है। 2012-2017 की रूपरेखा में तय लक्ष्य से देश बहुत पीछे रह गया है।

क्या है

1. सीएजी ने कहा है कि पीछे रह जाने के कारणों में से एक संस्थागत प्रजनन में कमी है। गांव से स्वास्थ्य केंद्र का दूर होना और परिवहन की सुविधा का नहीं होना भी एक कारण है।
2. कई राज्यों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रजनन सुविधा है ही नहीं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और त्रिपुरा के 50 फीसदी केंद्रों में ऐसी ही स्थिति है।
3. असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में 50 से 80 फीसदी घरेलू प्रजनन में प्रशिक्षित प्रसव सहायिका नहीं होती है।
4. इसी तरह हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल और मेघालय में 80 फीसदी से ज्यादा घरेलू प्रजनन में प्रशिक्षित प्रसव सहायिका नहीं होती है।
5. देश के 4,862 बड़े बांधों में से केवल 349 के पास ही आपदा कार्रवाई योजना है। जल संसाधन मंत्रालय की बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबंधन योजना की प्रदर्शन रिपोर्ट में सीएजी ने इस तथ्य को रेखांकित किया है।

- देश के शीर्ष लेखा परीक्षक ने कहा है कि जांच के लिए चुने गए 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केवल हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ही ऐसे हैं जिसने मानसून से पहले और बाद में बांधों की जांच की थी। तीन राज्यों ने आंशिक जांच की।

द्वीप विकास एजेंसी (आईडीए) की पहली बैठक

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नवगठित द्वीप विकास एजेंसी (आईडीए) की पहली बैठक की अध्यक्षता की। आईडीए की स्थापना द्वीपों के विकास के लिए प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद 01 जून 2017 को की गई थी। गृह मंत्री ने सुरक्षा चिंताओं को दूर करते हुए प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणाली की रक्षा करने के साथ-साथ भारत के समुद्रों के निकट अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक विजन प्रस्तुत किया। उन्होंने लोगों की भागीदारी के साथ द्वीपों के निरंतर विकास की आवश्यकता पर बल दिया।

क्या है

- नीति आयोग के सीईओ ने वर्तमान स्थिति और पहचाने गए द्वीपों के समग्र विकास के कार्य को आगे बढ़ाने के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने जानकारी दी कि निरन्तरता के सिद्धान्त, लोगों की भागीदारी, पारिस्थितिकी प्रणाली की रक्षा और दिशा निर्देश सिद्धान्तों के रूप में क्षमता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता के साथ संकल्पना विकास योजनाएं और विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। देश में इस तरह का कार्य पहली बार हाथ में लिया गया है।
- पूर्व नौ सेनाध्यक्ष और आईडीए के वाइस चेयरमैन एडमिरल डी.के.जोशी ने सुनियोजित परियोजनाओं के निरन्तर कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त कदम उठाने का सुझाव दिया।
- बैठक के दौरान समन्वित मास्टर प्लानों और द्वीप विकास से जुड़े अन्य मामलों को अमल में लाने के लिए हुई प्रगति की समीक्षा की गई। यह भी फैसला किया गया कि अण्डमान निकोबार द्वीप के उपराज्यपाल और लक्ष्यद्वीप के प्रशासक को आईडीए के सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।
- प्रमुख साझेदारों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद पहले चरण में 10 द्वीपों अण्डमान और निकोबार तथा मिनीकॉय में स्मिथ, रोस, एक्स, लोंग एण्ड लिटिल अण्डमान, लक्ष्यद्वीप में बंगाराम, सुहेली, चेरियम और टिन्नाकारा की समग्र विकास के लिए पहचान की गई। इस बैठक के साथ भारत के द्वीपों के समग्र विकास को काफी गति मिली है।
- आईडीए के अन्य सदस्यों मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, सचिव (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन), सचिव (पर्यटन) और सचिव (जन-जातीय कल्याण) ने भी बैठक में भाग लिया।

डीएनए नया मसौदा

डीएनए का बेजा इस्तेमाल न हो इसके लिए लॉ कमीशन ने नया मसौदा तैयार किया है। सरकार के पास सिफारिश भेजी गई है। अब इस पर नया कानून बनाया जा सकता है। कमीशन का मानना है कि किसी व्यक्ति का डीएनए टेस्ट केवल पहचान को उजागर करने के लिए हो।

क्या है

- लॉ कमीशन ने डीएनए आधारित तकनीकी बिल 2017 भी तैयार किया है। उसे इस बात की प्रबल आशंका है कि स्वास्थ्य संबंधी डाटा का दुरुपयोग भी हो सकता है।
- इससे किसी व्यक्ति विशेष की निजता प्रभावित न हो इसके लिए कमीशन ने सरकार से सिफारिश की है कि डाटा स्टोर करने के लिए बैंक बनाए जाए।
- राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर इन्हें केंद्र सरकार स्थापित करे। बैंक पूरी तरह से डाटा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे।
- कमीशन ने एक नया बोर्ड गठित करने का सुझाव दिया है, जिससे डीएनए जांच पर आधारित प्रयोगशालाओं को बनाने का काम ठीक तरीके से हो सके।

5. उसका मानना है कि उन्हीं प्रयोगशालाओं में जांच की जाए जो मानकों पर खरी उतरती हो। पुलिस के साथ अन्य जांच एजेंसियों के लिए दिशानिर्देश जारी करने का काम ये बोर्ड करेगा। इससे विवेचना बेहद प्रभावी तरीके से हो सकेंगी।

केंद्र ने दी न्यूनतम वेतन विधेयक को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए वेतन विधेयक (नए वेज कोड बिल) को मंजूरी दे दी है, जिससे देशभर में चार करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसमें मजदूरों से जुड़े चार कानूनों को मिलाया गया है, इससे सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित होगी। वेतन लेबर कोड बिल में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, वेतन भुगतान कानून 1936, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को एक साथ जोड़ा गया है। मसौदे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है।

क्या है

1. इस विधेयक में केंद्र सरकार को सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का अधिकार देने की बात कही गई है। साथ ही उसके फैसले को सभी राज्यों को मानना होगा। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी से अधिक राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्र के हिसाब से बढ़ा सकती हैं। इस बिल को 11 अगस्त को समाप्त हो रहे मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा।
2. नए न्यूनतम मजदूरी मानदंड सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। फिलहाल केंद्र और राज्य का निर्धारित न्यूनतम वेतन उन कर्मचारियों पर लागू होता है, जिन्हें मासिक 18,000 रुपये तक वेतन मिलता है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार सभी उद्योगों के श्रमिकों के लिए एक न्यूनतम वेतन तय हो सकेगा। इसमें वो भी शामिल हो जाएंगे, जिन्हें 18,000 रुपये से अधिक वेतन मिलता है।
3. श्रमिकों पर द्वितीय राष्ट्रीय आयोग ने सिफारिश की है कि मौजूदा मजदूर कानूनों को व्यापक रूप से कामकाज के आधार पर चार या पांच लेबर कोड्स में बांटा जाना चाहिए।
4. मंत्रालय मजदूरी पर चार लेबर कोड्स को ड्राफ्ट करने वाला है, जिसमें औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और सुरक्षा, और कामकाजी परिस्थितियां, शामिल हैं।

भारत के हाथ लगा कीमती धातुओं का भंडार

भारतीय वैज्ञानिकों को समुद्र के नीचे एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिऑलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने पानी के नीचे भारतीय प्रायद्वीप के आसपास लाखों टन कीमती धातुओं और खनिजों को ढूंढ निकाला है। हालांकि इस धातुओं और खनिजों की खोज में काफी लंबा समय लगा।

क्या है

1. पहली बार लगभग 2014 में मंगलुरु, चेन्नई, मन्नार बसीन, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के आसपास समुद्री संसाधनों को खोजा गया था। लगभग तीन सालों की खोज के बाद जिऑलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 181,025 वर्ग किमी का हाई रेजॉल्यूशन सीबेड मोरफोलॉजिकल डेटा तैयार किया है और 10 हजार मिलियन टन लाइम मड के होने की बात कही है।
2. जिस मात्रा में वैज्ञानिकों के हाथ लाइम मड, फोस्फेट-रिच और हाइड्रोकार्बन्स जैसी चीजें मिली हैं, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है पानी के और भीतर वैज्ञानिकों को और बड़ी सफलता मिल सकती है।
3. जीएसआई के सुपरिंटेंडेंट जिऑलॉजिस्ट आशीष नाथ ने बताया कि इसका मुख्य मकसद मिनरलाइजेशन के संभावित इलाकों की पहचान करना और मरीन मिनरल सांसधनों का आकलन करना है।

वैश्विक स्वास्थ्य के लिए 'मेड इन इंडिया'

देश में विकसित नवजात श्रवण स्क्रीनिंग उपकरण - सोहम का नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री श्री वाईएस चौधरी ने औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। नवजात श्रवण स्क्रीनिंग उपकरण को स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायो डिजाइन (एसआईबी) के स्टार्टअप मैसर्स सोहम इनोवेशन लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने विकसित किया है।

क्या है

1. यह अभिनव चिकित्सा उपकरण, बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन विकसित किया गया है।
2. एसआईबी डीबीटी का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य भारत की नैदानिक आवश्यकताओं के अनुसार अभिनव और सस्ते चिकित्सा उपकरणों को विकसित करना तथा भारत में चिकित्सा प्रौद्योगिकी आविष्कारकर्ताओं की अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करना है।
3. यह सरकार के मेक इन इंडिया अभियान में एक महत्वपूर्ण योगदान है। एम्स और आईआईटी दिल्ली ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के सहयोग से संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को लागू किया गया है। बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड इस कार्यक्रम की तकनीकी और कानूनी गतिविधियों का प्रबंधन करता है।
4. सोहम एक कम लागत वाला विशेष उपकरण है, जो मस्तिष्क की श्रवण की आवाज का उपयोग करता है और नवजात शिशु में सुनने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए श्रवण परीक्षण में स्वर्ण मानक है।
5. अभी तक, यह तकनीक बेहद महंगी है और अनेक लोगों के लिए इस तक पहुंच नहीं है। स्टार्टअप सोहम ने संसाधनों के लिए उपयुक्त यह तकनीक बनायी है और इसका उद्देश्य देश में प्रति वर्ष पैदा होने वाले लगभग 26 मिलियन बच्चों की जरूरत पूरा करना है।
6. श्रवण बाधिता जन्म विकारों में से एक सबसे प्रमुख विकार है **जन्म से ही सुनाई न देना, आनुवांशिक और गैर-आनुवांशिक दोनों कारकों का ही परिणाम है।**
7. ये कारक भारत में ज्यादातर संसाधन रूप से गरीब अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े हैं। उन्नत स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के विपरीत, श्रवण बाधित का पता ही नहीं चल पाता। इस प्रकार, इसका पता बच्चे की उम्र चार वर्षसे अधिक होने पर पता चलता है, जब तब इस हानि को दूर करने में बहुत देर हो चुकी होती है। इससे कई बार बच्चे बोल पाने में भी असमर्थ होते हैं और मानसिक रूप से भी बीमार हो सकते हैं। इन सबका बच्चे पर गहरा कुप्रभाव पड़ता है तथा जन्म पर्यन्त खामियाजा भुगतना पड़ता है।
8. **विश्व स्तर पर हर साल लगभग 8,00,000 श्रवण रूप से दिव्यांग बच्चें पैदा होते हैं, जिनमें से करीब 1,00,000 भारत में पैदा होते हैं, इसलिए इस रोके जाने वाली क्षति की जल्दी स्क्रीनिंग किये जाने की आवश्यकता है, इससे समय पर उपचार और पुनर्वास की सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी।** सोहम की टीम ने नवजात शिशुओं की नियमित जांच करने के लिए एक स्क्रीनिंग उपकरण तैयार किया है, जिसमें बच्चों के महत्वपूर्ण चरण में विकास के लिए मदद प्रदान करने की संभावना है।
9. श्रवण स्क्रीनिंग बच्चे के सिर पर लगाये गये **तीन इलेक्ट्रोड के माध्यम से श्रवण मस्तिष्क की तरंग मापता है।** उत्तेजित होने पर ये इलेक्ट्रोड बच्चे की श्रवण प्रणाली द्वारा उत्पन्न विद्युत प्रतिक्रियाओं का पता लगाती हैं। अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, तो बच्चा सुन नहीं सकता।
10. **बैटरी संचालित उपकरण गैर-इनवेसिव है, जिसका अर्थ है कि शिशुओं को बेहोश करने की जरूरत नहीं है।** इस उपकरण का अन्य परीक्षण प्रणालियों की अपेक्षा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह पेटेंट और इन-बिल्ट एल्गोरिथम है, जो परीक्षण संकेत से परिवेश के शोर को बाहर निकालता है।

यूएनपीसीएपी-02 आरम्भ हुआ

संयुक्त राष्ट्र का शांति स्थापना केन्द्र (सीयूएनपीके), 17 जुलाई से 4 अगस्त 2017 तक नई दिल्ली में अमरीका के साथ संयुक्त रूप से अफ्रीकी भागीदारों के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना पाठ्यक्रम के दूसरे सत्र का आयोजन कर रहा है। इस पाठ्यक्रम का उद्घाटन 17 जुलाई को मानक शांति केन्द्र, नई दिल्ली में हुआ। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता श्रीमती रूचि घनश्याम, सचिव (पश्चिम), विदेश मंत्रालय ने की। उन्होंने अधिकारियों का स्वागत किया और उपस्थित लोगों को संयुक्त राष्ट्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की जानकारी दी।

क्या है

1. इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र को योगदान देने वाले देशों की अफ्रीकी सैनिक टुकडियों में क्षमताएं बनाना और उनमें वृद्धि करना तथा इन देशों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करना है।

2. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह पाठ्यक्रम मुख्य रूप से प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने की संकल्पना पर आधारित है, जो कि भारत द्वारा शांति स्थापना की गतिविधियों में किये गये सक्रिय योगदान के लिए उठाये गए कदमों में से एक है।
3. इस पाठ्यक्रम में भारत सहित 19 देशों के अधिकारी भाग ले रहे हैं। पाठ्यक्रम में शामिल प्रशिक्षु अधिकारी वर्तमान में अफ्रीकी शांति स्थापना प्रशिक्षण संस्थाओं के संबंधित शांति स्थापना प्रशिक्षण केंद्रों में तैनात हैं।
4. प्रशिक्षण में परिचालन और साजो सामान संबंधित मामले, मानवीय मुद्दे, संबंधित विषय और ब्लैक-बोर्ड एवं टेबल टॉप अभ्यास तथा अभियानों के संक्षिप्त विवरणों को शामिल किया गया है।
5. प्रशिक्षण में अपने संबंधित देशों में आगे प्रशिक्षण अधिकारियों को शांति स्थापना की बारीकियां समझाने में प्रशिक्षु अधिकारियों की सहायता के ऊपर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से इस पाठ्यक्रम को पहले ही कई मायनों में मील का पत्थर माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली 21 जुलाई को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) को औपचारिक तौर पर लॉन्च किये। यह पेंशन स्कीम खास तौर पर 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों के लिए है। लाइफ इन्श्यो रेंस कॉरपोरेशन (एलआईसी) से यह पेंशन प्लान ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से खरीदा जा सकता है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 4 मई 2017 को लॉन्च किया है।

क्या है योजना

1. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए तैयार की गई एक खास पेंशन योजना है जो कि 4 मई 2017 से 3 मई 2018 तक उपलब्ध होगी, यानी इस दौरान आप इस योजना को चुन सकते हैं।
2. वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) की ही तरह प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) उन वरिष्ठ लोगों के लिए एक पेंशन योजना है जिनकी उम्र 60 वर्ष के ऊपर है।
3. इस योजना के अंतर्गत 8 फीसद का सम एश्योर्ड रिटर्न भी सुनिश्चित किया गया है।

क्या हैं योजना के फायदे

1. मंत्रालय के मुताबिक यह पेंशन स्कीम 8 फीसद का एश्योर्ड रिटर्न उपलब्ध करवाएगी। यह स्कीम 10 साल के लिए है। यानी एक बार पेंशन प्लान ले लेने पर आपको अगले 10 सालों तक मासिक आधार पर पेंशन दी जाती रहेगी।
2. 10 साल की पॉलिसी टर्म से दौरान पेंशन हर अवधि के अंत में दी जाएगी, जैसा कि पेंशनल ने खरीद

इस पेंशन प्लान के अन्य फायदे:

1. यह स्कीम पूरी तरह से सर्विस टैक्स और जीएसटी के दायरे से बाहर है।
2. अगर पेंशनर पॉलिसी टर्म की अवधि यानी 10 साल तक जिंदा रहता है तो पर्चेज प्राइज के साथ ही फाइनल पेंशन की इंस्टॉलमेंट का भुगतान कर दिया जाएगा।
3. अगर किसी कारणवश पेंशनभोगी (पॉलिसी होल्डर) की मृत्यु हो जाती है तो, भुगतान किए गए प्रीमियम (खरीद मूल्य) पेंशनभोगी के नामित/ कानूनी उत्तराधिकारी को वापस कर दिए जाएंगे।
4. पॉलिसी के तीन साल पूरे हो जाने के बाद आपको पर्चेज प्राइज का 75 फीसद हिस्सा बतौर लोन भी मिल सकता है। लोन का ब्याज पेंशन की इंस्टॉलमेंट से पूरा कर लिया जाएगा और लोन की राशि क्लेम के दौरान रिकवर कर ली जाएगी।
5. स्कीम के तहत अगर पेंशनर को खुद या उसकी पत्नी को गंभीर बीमारी हो जाती है तो वह इस स्कीम से समय से पहले निकल सकता है। ऐसी सूरत में उसे पर्चेज प्राइज का 98 फीसदी रिफंड मिल जाएगा।

के दौरान मासिक, तिमाही, छमाही और सालाना आधार का चयन किया होगा।

भारत में होगी साइबर स्पेस पर वैश्विक कॉन्फ्रेंस

साइबर स्पेस पर पूरी दुनिया में सबसे बड़े सम्मेलन का आयोजन इस बार भारत में होगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि 5वें ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस 2017 का आयोजन 23 और 24 नवंबर को नई दिल्ली में होगी।

क्या है

1. इस कॉन्फ्रेंस का थीम साइबर फॉर ऑल होगा। प्रसाद ने बताया कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
2. भारत में इस कॉन्फ्रेंस का पहली बार आयोजन किया जा रहा है।
3. इसमें करीब 100 देशों से 2000 प्रतिनिधियों के आने की संभावना है।
4. इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत साल 2011 में हुई थी।
5. चौथी कॉन्फ्रेंस अप्रैल 2015 में नीदरलैंड के हेग में हुई थी।

एयर इंडिया के विनिवेश पर पहली बैठक

एयर इंडिया के विनिवेश के तौर तरीके तय करने के लिए गठित अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह की पहली बैठक हुई। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई बैठक में नागरिक विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू, रेल मंत्री सुरेश प्रभु तथा ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया। जीओएम के एक अन्य सदस्य सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उड़ीसा के दौरे पर होने के कारण बैठक में भाग नहीं ले सके। बैठक में चर्चा के लिए एयर इंडिया के सीएमडी अश्वनी लोहानी को भी बुलाया गया था।

क्या है

1. गौरतलब है कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने पिछले महीने के आखिर में एयर इंडिया के विनिवेश का सैद्धांतिक फैसला लिया था।
2. इसके बाद विनिवेश की प्रक्रिया व तौर तरीके तय करने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में पांच केंद्रीय मंत्रियों के जीओएम का गठन किया गया था।
3. जीओएम को एयर इंडिया के 52000 करोड़ रुपये के कर्ज, उसकी परिसंपत्तियों के अलावा लाभ कमा रही तीन सब्सिडियरियों के भविष्य के बारे में निर्णय लेने हैं। उसे यह भी देखना है कि विनिवेश पूर्ण रूप से हो या आंशिक रूप से।
4. एयर इंडिया पर कर्ज के अलावा 50 हजार करोड़ रुपये के संचित घाटे का भी बोझ है। जिसे कम करने के लिए पिछली संप्रग सरकार ने 2012 में 30 हजार करोड़ रुपये के दस वर्षीय पुनरुद्धार पैकेज का ऐलान किया था। पैकेज की अधिकांश राशि एयर इंडिया को दी जा चुकी है।

व्हाट्सएप की नई प्राइवैसी पॉलिसी से होगा निजता का हनन

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि व्यक्तिगत डेटा एक व्यक्ति के जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा होता है और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं या सोशल नेटवर्किंग साइट्स द्वारा स्वतंत्र रूप से साझा नहीं किया जा सकता है। विकास ऐसे समय में आता है जब एक बहस गोपनीयता के अधिकार के बारे में है और सर्वोच्च न्यायालय से पहले ही सरकार द्वारा उठाए गए स्टैंड के विपरीत है, आधार मामलों में नागरिकों के पास गोपनीयता का मूल अधिकार नहीं है।

क्या है

1. दरअसल, एक शख्स की ओर से दाखिल याचिका में व्हाट्सएप की नई प्राइवैसी पॉलिसी का विरोध किया गया है। उन्होंने याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप की ओर से अपने यूजर्स की जानकारी फेसबुक से साझा करना निजता के अधिकार का हनन है।
2. केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ता की बात का समर्थन करते हुए कहा किसी के निजी डाटा को व्यावसायिक फायदे के लिए शेयर करना गलत है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पी एस नरसिम्हा ने कहा कि निजी डाटा जीवन के अधिकार का ही एक पहलू है।

3. एडिशनल सॉलिसिटर ने कहा, मेरा (व्यक्तिगत) व्यक्तिगत डेटा मेरे लिए अंतरंग है यह सम्मान के साथ जीवन जीने का मेरे अधिकार का एक अभिन्न अंग है।
4. यदि किसी व्यक्तिगत और इंटरनेट सेवा प्रदाता के बीच कोई अनुबंध इसे साझा करने के लिए होता है, तो यह व्यक्ति के अधिकार (अनुच्छेद 21 के तहत) का कहना है। ऐसे में राज्य को इस तरह के डेटा को बांटने में हस्तक्षेप और विनियमन करना होगा।
5. उधर व्हाट्सऐप की तरफ से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि टेलिकॉम कंपनियां व्हाट्सऐप जैसी सेवाओं के विस्तार से घबरा कर इस तरह की याचिकाएं दाखिल करवा रही हैं।

पांचवी पीढ़ी का मिग-35 लड़ाकू विमान

रूस पांचवी पीढ़ी का मिग-35 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को बेचने का इच्छुक है, भारत रुचि दिखाए तो सौदा पक्का हो सकता है। यह बात मिग कॉर्पोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) इल्या तारासेंको ने कही है। इसी साल जनवरी में लांच हुआ यह अत्याधुनिक विमान अमेरिकी विमान एफ-35 से कई मायनों में बेहतर माना जा रहा है। इसके सिस्टम कुछ वैसे ही हैं जैसे कि मिग-29 के हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना कर रही है।

क्या है

1. रूस के झुकोवस्की शहर में चल रहे माक्स 2017 एयर शो के दौरान बातचीत में सीईओ तारासेंको ने कहा, उनकी कंपनी भारतीय वायुसेना की जरूरतों के मुताबिक उसके खरीद आदेश को प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रही है। दोनों पक्ष अभी तकनीक मामलों पर बातचीत की प्रक्रिया में हैं।
2. मिग कंपनी प्रमुख ने कहा, भारत उनके विमानों का पिछले 50 साल से इस्तेमाल कर रहा है। उनकी इच्छा है कि वह कंपनी का अत्याधुनिक उत्पाद भी खरीदे और उसका इस्तेमाल करे।
3. विमान के मूल्य के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, बिक्री के बाद सेवा देने के पक्ष को शामिल कर लिया जाए तो यह सस्ता पड़ेगा। हम बिक्री के साथ ही इसकी 40 साल तक सर्विस का समझौता भी कर रहे हैं। इस लिहाज से यह दुनिया के समकक्ष विमानों की तुलना में 20 से 25 प्रतिशत सस्ता पड़ रहा है।
4. मिग-35 रडार की पकड़ में न आने वाला स्टील्थ विमान है। इसकी खासियतें इसे पांचवीं पीढ़ी के नजदीक ले जाती हैं। इसमें तीन तरह के मिसाइल सिस्टम लगे हैं। जो हवा, जमीन और पानी में मार कर सकते हैं। इसका डिफेंस सिस्टम भी काफी मजबूत है।

धारा 498 ए में अब सीधे गिरफ्तारी नहीं

दहेज प्रताड़ना निरोधक कानून की धारा 498 ए के हो रहे दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को व्यापक दिशानिर्देश जारी किए। अब दहेज प्रताड़ना के मामले पुलिस के पास न जाकर एक मोहल्ला कमेटी (सिविल सोसायटी) के पास जाएंगे, जो उस पर अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही पुलिस देखेगी कि कार्यवाही की जाए या नहीं।

क्या है

1. शीर्ष अदालत द्वारा जारी इन निर्देशों के लागू होने के छह माह बाद 31 मार्च 2018 को विधिक सेवा प्राधिकरण परिवर्तन करने के लिए सुझाएगा। मामले की सुनवाई अप्रैल 2018 में होगी।
2. अदालत के आदेश की प्रति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, सभी डीजीपी, सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कार्यवाही के लिए भेज दी जाएगी।
3. सुप्रीम कोर्ट ने दो वर्ष पूर्व एक फैसले में आदेश दिया था कि दहेज प्रताड़ना के मामले में पुलिस आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार नहीं करेगी।
4. जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने उत्तरप्रदेश के एक मामले में दिए फैसले में कहा कि धारा 498ए को कानून में रखने का (1983 संशोधन) मकसद पत्नी को पति या उसके परिजनो के हाथों होने वाले अत्याचार से बचाना था। वह भी तब जब ऐसी प्रताड़ना के कारण पत्नी के आत्महत्या करने की आशंका हो।

5. अदालत ने कहा कि यह चिंता की बात है कि विवाहिताओं द्वारा धारा 498ए के तहत बड़ी संख्या में मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। स्थिति को हल करने के लिए हमारा मत है कि इस मामले में सिविल सोसाइटी को शामिल किया जाए, ताकि न्याय के लिए प्रशासन को कुछ मदद मिल सके। यह भी देखना होगा कि जहां वास्तव में समझौता हो गया है, वहां उचित कदम उठाया जाए। इससे पक्षों को इसे समाप्त करने के लिए हाईकोर्ट न जाना पड़े।

ये है मामला

1. उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के इस मामले में पत्नी पक्ष ने धारा 498ए के तहत एफआईआर में पति राजेश शर्मा के सभी परिजनों भाई-बहन, माता-पिता का नाम लिखवा दिया था।
2. आरोप था कि उन्होंने तीन लाख रुपये और कार की मांग पर उसे प्रताड़ित किया। मामले में जारी समन को रद्द करने के लिए वे सुप्रीम कोर्ट आए थे। कोर्ट ने इस मामले में एएसजी एएस नाडकर्णी और वी. गिरी को लेकर कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ये निर्देश जारी किए गए।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ खड़ा है भारत

भारत ने संयुक्त राष्ट्र परिषद द्वारा जिनेवा स्थित एक मानवाधिकार एनजीओ को परामर्शदात्री का दर्जा देने से इनकार करने के निर्णय का समर्थन किया है, जिसे संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) ने 26 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आपत्तियों के बाद फाउंडेशन अलकामा को परामर्शदात्री का दर्जा देने से इनकार करने का फैसला किया। यूएई समेत सऊदी अरब, बहरीन

और मिस्र ने नौ संगठनों और नौ व्यक्तियों की एक नई सूची जारी की है, जिसे लेकर दावा किया गया है कि वे कतर द्वारा समर्थित और कथित रूप से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं।

ये दिशा-निर्देश लागू होंगे

1. सुप्रीम कोर्ट ने कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर जिले में एक परिवार कल्याण कमेटी गठित करेगी, जिसमें तीन सदस्य होंगे।
2. इस कमेटी के कार्य की जिला एवं सत्र न्यायाधीश समय-समय पर और कम से कम एक वर्ष में समीक्षा करेंगे। जबकि कमेटी में अर्द्धविधिक स्वयंसेवी/ सामाजिक कार्यकर्ता/ पूर्व कर्मी/ कार्यरत कर्मियों या अन्य नागरिकों की पत्नियां भी सदस्य होंगी। कमेटी के सदस्यों को गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाएगा।
3. धारा 498ए के तहत आई प्रत्येक शिकायत पुलिस या मजिस्ट्रेट इस कमेटी के पास भेजेंगे। कमेटी परिवार के सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से, फोन, मेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों से बातचीत करेगी।
4. इसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट एक माह में मजिस्ट्रेट या पुलिस को भेजेगी, जिसमें उसकी तथ्यात्मक राय होगी। कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने तक पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी।
5. साथ ही रिपोर्ट पर पुलिस जांच अधिकारी या मजिस्ट्रेट उसके गुणदोष को लेकर विचार करेंगे। कमेटी के सदस्यों को विधिक सेवा प्राधिकरण समय-समय पर बुनियादी प्रशिक्षण देगा और उन्हें उचित मेहनताना भी दिया जाएगा। उनके मेहनताने के लिए जिला एवं सत्र जज जुर्माना राशि से फंड ले सकते हैं।
6. धारा 498ए के तहत मिली शिकायत पर क्षेत्र के निर्दिष्ट अधिकारी जांच करेंगे। ऐसे अधिकारी को पुलिस एक माह के अंदर नियुक्त करेगी और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा।
7. समझौता हो चुके मामलों में जिला एवं सत्र जज कार्यवाही समाप्त करेंगे। देश से बाहर रह रहे आरोपियों के पासपाट जब्त या रेड कॉर्नर नोटिस रूटीन में जारी नहीं किए जाएंगे।
8. मामले से जुड़े सभी केस एक ही अदालत में रखे जाएंगे, ताकि जज को इसकी पूरी जानकारी रहे।
9. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि उसके ये निर्देश उन मामलों में लागू नहीं होंगे, जहां पीड़ित के शरीर पर चोटों के निशान मिले हों या उसकी मृत्यु हो गई हो।

क्या है

1. भारत सहित कई देशों ने इस एनजीओ की गतिविधियों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि वे आतंकवाद से लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ खड़ा है।
2. भारत की प्रतिनिधि पॉलोमी त्रिपाठी ने परिषद की बैठक के दौरान कहा कि यूएई ने अलकामा के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है और इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है।
3. उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद से लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करेगा और इस तरह की चिंता को गंभीरता से लेता है।
4. त्रिपाठी ने परामर्शदात्री स्थिति से इनकार करने के फैसले का समर्थन किया और जोर देकर कहा कि समिति के कामकाज पर आत्मनिरीक्षण की जरूरत है।
5. मौजूदा स्थिति को देखते हुए सलाहकार तंत्र में पर्याप्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, हमें आवेदनों की बहुत अधिक जांच-परख करने की आवश्यकता है।
6. वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अलकामा 2004 में स्थापित एक जिनेवा स्थित मानवाधिकार एनजीओ है, जो कि अरब देशों में उन सभी लोगों की सहायता करता है जो संकट में हैं, यातनाएं झेल रहे होते हैं या जिन्हें मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जाता है।

पोखरण में हो रहा है अल्ट्रा-लाइट होवित्जर तोपों का परीक्षण

राजस्थान के पोखरण में लंबी दूरी तक मार करने वाले दो अल्ट्रा-लाइट होवित्जर तोपों का परीक्षण हो रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि बोफोर्स कांड के 30 साल बाद भारतीय सेना को अमेरिका से ये तोपें मिली हैं। उम्मीद की जा रही है कि इनमें से ज्यादातर तोपों को चीन से लगी सीमा पर तैनात किया जाएगा।

क्या है

1. तोपों के इन परीक्षणों का प्राथमिक उद्देश्य एम-777 ए-2 अल्ट्रा-लाइट होवित्जर के प्रक्षेप पथ, रफ्तार और गोले दागने की फ्रीक्वेन्सी जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण डेटा जमा करना एवं नियत करना है।
2. परीक्षण की जानकारी रखने वाले एक सैन्य अधिकारी ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया कि ये परीक्षण सितंबर तक जारी रहेंगे।
3. 155 मिलीमीटर, 39-कैलिबर के तोप में भारतीय आयुध उपयोग किए जाएंगे। 2018 के सितंबर में सेना को प्रशिक्षण के लिए तीन और तोपों की आपूर्ति होगी। इसके बाद 2019 के मार्च महीने से सेना में प्रति माह पांच तोपों की तैनाती शुरू हो जाएगी।
4. तोपों की आपूर्ति 2021 के मध्य में पूरी हो जाएगी और इसी के साथ इसकी तैनाती भी पूरी हो जाएगी।
5. भारत ने 5000 करोड़ रुपये की लागत से 145 होवित्जर तोपों की आपूर्ति के लिए पिछले साल नवंबर में अमेरिका के साथ एक समझौता किया था। इसी के तहत सेना को मई में ये तोप मिले।

अन्तरराष्ट्रीय

चीन के नाम हंबनटोटा पोर्ट

श्रीलंका-चीन के बीच एक बंदरगाह को लेकर हुआ यह समझौता भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। श्रीलंका ने हंबनटोटा बंदरगाह की 70 फीसद हिस्सेदारी चीन मर्चेन्ट पोर्ट होल्डिंग्स को 1.12 बिलियन डॉलर (करीब 72 अरब रुपये) में बेच दी है। इस समझौते पर महीनों बाद मुहर लगी।

क्या है

1. श्रीलंका को यह आशंका थी कि इस बंदरगाह का चीनी नौसेना उपयोग कर सकती है। चीन ने श्रीलंका में समाप्त हुए गृह युद्ध के बाद वहां करोड़ों रुपये का निवेश कर रखा है।
2. चीनी कंपनी को बंदरगाह 99 साल की लीज पर दी गई है। हालांकि भारत के लिए यह राहत पहुंचाने वाली खबर है कि हंबनटोटा बंदरगाह की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह श्रीलंकाई नौसेना पर होगी।

3. माना जा रहा है कि सौदे में इस शर्त को शामिल कर श्रीलंका ने भारत की सामरिक चिंताओं को ध्यान में रखा है।
4. इस डील को लेकर श्रीलंका सरकार को ट्रेड यूनियनों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। यूनियनों ने सरकार पर आरोप लगाया था कि देश की संपत्ति चीन को बेची जा रही है।
5. बीते सप्ताह पेट्रोलियम आपूर्ति से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल से श्रीलंका का जनजीवन ठप पड़ गया था। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने समझौते पर कहा, हम देश के लिए बेहतर सौदा कर रहे हैं। बंदरगाह की 70 फीसद हिस्सेदारी बेचने से जो पैसा मिलेगा, उसे चीन का कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

अमेरिका का यह हाइपरसॉनिक मिसाइल

अमेरिका ऐसे हाइपरसॉनिक एयरक्राफ्ट मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, जो एक मील प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ सकेगा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मिलकर यह मिसाइल विकसित कर रहे हैं। यह हाइपरसॉनिक मिसाइल आवाज की गति की तुलना में कम से कम 5 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से चल सकेगा। इसकी गति 6,200 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 12,391 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो सकती है। X-51। वेवराइडर नाम के इस मिसाइल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसकी रफ्तार बढ़कर 12,391 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है।

क्या है

1. इस कार्यक्रम का नाम हाइपरसॉनिक इंटरनैशनल फ्लाइट रिसर्च एक्सपेरिमेंटेशन (HiFIRE) प्रोग्राम रखा गया है।
2. दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के वूमेरा परीक्षण रेंज में अबतक कम से कम हाइपरसॉनिक उड़ान का सफल परीक्षण होने की जानकारी है। परीक्षणों का यह दौर 12 जुलाई को पूरा हुआ।
3. साढ़े 3 अरब रुपये (54 मिलियन डॉलर्स) की इस योजना में अमेरिकी वायुसेना, बोइंग, ऑस्ट्रेलिया का रक्षा विज्ञान व तकनीक विभाग, BAE सिस्टम्स ऑस्ट्रेलिया और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन्सलैंड शामिल हैं।
4. रूस और चीन भी हाइपरसॉनिक ग्लाइड विमान बना रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना के जनरल जॉन हेटन ने हाल ही में US कांग्रेस के सामने यह बात कही थी।
5. कई बलिस्टिक मिसाइल इससे भी तेज गति से उड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे मिसाइलों का प्रक्षेप पथ उपग्रहों द्वारा आसानी से पता लगाया जा सकता है। अमेरिका के पास ऐसे अवरोधक हैं, जो कि ऐसे बलिस्टिक मिसाइलों को बीच रास्ते में ही खत्म कर सकते हैं। इनके मुकाबले हाइपरसॉनिक हथियार ज्यादा कारगर साबित होते हैं। ऐसा इसलिए कि इन्हें ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है।

योंगशिंग द्वीप पर खुला सिनेमा हॉल

विवादित दक्षिण चीन सागर पर अपने अधिकार को मजबूत करने के लिए चीन कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इसी सिलसिले में उसने अब दक्षिण चीन सागर के योंगशिंग द्वीप पर आधुनिक सिनेमा हॉल खोला है। सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, यह सिनेमाघर दक्षिण चीन सागर में चीन के नए शहर सांशा में खोला गया है। इसका नाम सांशा यिनलांग सिनेमा रखा गया है। इसमें 200 से अधिक स्थानीय निवासियों और सैनिकों ने चीनी फिल्म द इटर्निटी ऑफ जियाओ युलू का पहला शो देखा।

क्या है

1. हैनान मीडिया क्रूप के महाप्रबंधक गू शिओजिंग ने कहा, सिनेमा हॉल में रोजाना एक फिल्म दिखाई जाएगी। इससे योंगशिंग द्वीप पर रहने वाले लोग और सैनिक भी देश के दूसरे नागरिकों की तरह फिल्म का मजा ले सकते हैं।
2. शिन्हुआ के अनुसार यह सिनेमा हॉल उन्नत उपकरणों से सुसज्जित है। इसमें आधुनिक 4के डिजिटल प्रोजेक्टर के साथ ही 3डी स्क्रीन भी है। इससे दर्शकों को बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का भरपूर मजा मिलता है।

3. गौरतलब है कि चीन विवादित क्षेत्र में अपने कब्जे वाले द्वीपों पर लोगों को बसाने के साथ ही सुविधाओं का भी विस्तार कर रहा है। वह इस क्षेत्र में कई कृत्रिम द्वीप भी बना चुका है।
4. इनमें से कई पर उसने सैन्य अड्डे और हवाई पट्टी भी बना ली है। दक्षिण चीन सागर पर वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी अपना दावा करते हैं।

संसदीय पैनल में शामिल हुई पहली महिला

ब्रिटेन के संसदीय चयन समिति में पहली बार सिख महिला सांसद प्रीत कौर गिल को चुना गया है। यह चयन समिति गृह कार्यालय के कामकाज का निरीक्षण करती है। प्रीत लेबर पार्टी की सांसद हैं और इन्होंने बर्मिंघम एबेस्टन सीट से वर्ष 2017 में चुनाव जीता है। प्रीत उन 11 सांसदों में से एक हैं, जो गृह मंत्रालय के क्रिया कलाप को देखेंगी।

क्या है

1. लेबर पार्टी की सांसद कैथ वैज नौ साल के लिए इस चयन समिति की अध्यक्ष थीं, लेकिन पिछले साल सितंबर में उन्हें ड्रग्स और देह व्यापार के मामले में सलिप्त होने के आरोपों के कारण पद छोड़ना पड़ा।
2. ब्रिटिश सिखों के लिए ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप (APPG) का नेतृत्व के लिए भी गिल को चुना गया है।
3. यह ग्रुप भारत और ब्रिटेन के सांसदों और लोगों के बीच सहयोग व समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है।

नेताजी की मौत पर फ्रांस की रिपोर्ट

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के रहस्य पर से पर्दा माना जा रहा था कि उठ गया है। जिस तरह से भारत सरकार ने नेताजी से जुड़े तमाम दस्तावेजों को सार्वजनिक किया और उसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि नेताजी की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी, उसके बाद माना जा रहा था कि यह विवाद अब खत्म हो गया है। लेकिन फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट ने दावा किया है कि नेताजी की मौत हवाई हादसे में नहीं हुई है।

क्या है

1. फ्रांस की एक खुफिया रिपोर्ट ने दावा किया है कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, पेरिस के इतिहासकार जेबीपी मूर का दावा है कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई है।
2. मूर का कहना है कि नेताजी की मौत ताइवान के प्लेन क्रैश में नहीं हुई है, बल्कि नेताजी के ठिकाने के बारे में दिसंबर 1947 तक पता नहीं था।
3. मूर के दावे के बाद एक बार फिर से यह साफ हो जाता है कि फ्रांस नेताजी के प्लेन क्रैश में 18 अगस्त 1945 में मारे जाने के दावे को मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि मूर पेरिस के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में प्रोफेसर हैं।
4. फ्रांस की खुफिया विभाग का मानना है कि बोस 18 अगस्त 1947 में प्लेन क्रैश में नहीं मारे गए थे, बल्कि वह इंडो-चीन से बच निकलने में सफल हुए थे, उनके ठिकाने के बारे में 11 दिसंबर 1947 तक किसी को पता नहीं था। इससे साफ है कि वह कहीं ना कहीं 1947 तक जिंदा थे।

वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (WFP) का रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (WFP) ने 17 जुलाई को कुपोषण पर जारी एक रिपोर्ट में कहा है कि, पश्चिमी म्यांमार के मुस्लिम बहुल इलाके में पांच वर्ष से कम उम्र के 80,000 बच्चे भूखमरी और कुपोषण से मर रहे हैं। रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि अगले साल तक इन बच्चों के इलाज की सख्त जरूरत है वरना स्थिति और भी भयावह हो सकती है।

क्या है

1. यूएन एजेंसी की यह रिपोर्ट राखिनी राज्य में किए गए सर्वे पर आधारित थी जहां आर्मी हमलों के बाद 75,000 मुस्लिम पलायन कर गए थे। उनमें से जो बच गए वे खाने-खाने को तरस रहे हैं।

2. एजेंसी ने सर्वे में ये पाया कि एक तिहाई घरों में खाद्य पदार्थों के लाले पड़े हैं, जबकि एक जिला पूरी तरह से हिंसा की चपेट में आ चुका है।
3. रिपोर्ट के अनुसार, स्थिति ऐसी है कि किसी के पास खाने को कुछ नहीं है। दो वर्ष के एक भी बच्चे को समुचित भोजन नहीं मिल पा रहा है, जबकि 225,000 लोगों को मानवीय सहायता की सख्त जरूरत है।
4. डब्ल्यूएफपी रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा, सर्वेक्षण में खाद्य सुरक्षा की स्थिति में पहले से ही संवेदनशील स्थिति पाई गई जो 2016 के आखिर में हिंसा की घटनाओं के बाद हालात और बिगड़ गए।
5. पिछले अक्टूबर में, सीमा पुलिस पर रोहिंगिया आतंकवादी हमलों के बाद सेना के साथ मुठभेड़ में काफी क्षेत्र हिंसा से प्रभावित हुए थे।
6. सर्वे में पाया गया कि हिंसा के बाद इन क्षेत्रों में खाद्य कीमतों में काफी अस्थिरता आ गई और प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थों की आपूर्ति भी दुर्लभ हो गई।

डोकलाम पर तनातनी के बीच चीन ने किया सैन्य अभ्यास

सिक्किम से लगी भारतीय सीमा पर पैदा हुए तनाव के माहौल में चीन तिब्बत के पर्वतीय इलाके में सैन्य अभ्यास कर रहा है। इस दौरान चीन की सेना ने हथियारों से असली कारतूस और गोले दागकर अभ्यास किया। आमतौर पर इस तरह का अभ्यास नकली या मामूली असर वाले गोला-बारूद से होता है।

क्या है

1. सिक्किम सेक्टर के डोकलाम में भारतीय सेना ने चीन को सड़क बनाने से रोक दिया है और बाकायदा तंबू लगाकर इलाके की निगरानी कर रही है। बौखलाए चीन ने तीखी बयानबाजी के बाद अब तिब्बत के पर्वतीय इलाके में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है।
2. यह इलाका भौगोलिक रूप से विवादित इलाके जैसा ही है और माना जा रहा है कि इस अभ्यास का डोकलाम विवाद से सीधा संबंध है। चीन के सरकारी टेलीविजन के अनुसार चीनी सेना ने वहां पर 11 घंटे तक लगातार सैन्य अभ्यास किया।
3. जिस ब्रिगेड ने अभ्यास किया, वह चीन की दो पर्वतीय ब्रिगेडों में से एक है। इस ब्रिगेड की आमतौर पर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर तैनाती रहती है और यह मोर्चे पर हमलावर भूमिका निभाने के लिए प्रशिक्षित है। युद्धाभ्यास में दुश्मन के विमान खोजने वाले रडार का इस्तेमाल भी किया गया और विमानभेदी तोपें भी दागी गईं। इससे पहले दस जुलाई को तिब्बत मोबाइल कम्युनिकेशन एजेंसी ने ल्हासा में अभ्यास किया था।
4. उसने युद्ध की स्थितियों के लिए अपनी क्षमताएं परखी थीं। इससे पहले खबर आई थी कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत के पर्वतीय इलाकों में कई नए हथियारों का भी परीक्षण किया। इनमें हल्के वजन के टैंक भी शामिल थे।

अर्थशास्त्र

फिनो पेमेंट बैंक की औपचारिक शुरुआत

भारतीय रिजर्व बैंक की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद फिनो पेमेंट बैंक ने देश के 14 राज्यों में 410 शाखाओं के साथ परिचालन शुरू कर दिया। बैंक का शुभारंभ औपचारिक तौर पर आइसीआइसीआइ बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर व सीईओ चंदा कोचर और बीपीसीएल के सीएमडी डी. राजकुमार ने किया।

क्या है

1. फिनो पेमेंट बैंक ने 410 शाखाओं के अलावा 25000 बैंकिंग प्वाइंट का व्यापक नेटवर्क भी तैयार किया गया है। बीपीसीएल के 20000 आउटलेट भी बैंकिंग प्वाइंट के तौर पर पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का हिस्सा होंगे।
2. इससे दूरदराज के क्षेत्रों में बैंक की पहुंच सुनिश्चित होगी।

3. पहले साल में बैंक की योजना 30 से 40 लाख ग्राहकों को जोड़ने की है। पांच साल में पांच करोड़ ग्राहकों के साथ बैंक ने अपना जमा आधार 100 अरब रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

मुनाफाखोरी रोधक प्राधिकरण के लिए बनी समिति

जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी के अंतर्गत मुनाफाखोरी के खिलाफ राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्तियों की पहचान और सिफारिश करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया है। मुनाफाखोरी के खिलाफ राष्ट्रीय प्राधिकरण का कार्य उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह पर कर में कटौती का पूर्ण लाभ सुनिश्चित करना है।

क्या है

1. जीएसटी परिषद की तरफ से गठित होने वाला यह प्राधिकरण वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी की दर में कटौती अथवा यदि मूल्यों में अनुपातिक कटौती द्वारा प्राप्तकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दिये जाने की स्थिति में मुनाफा कमाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होगा।
2. इस प्राधिकरण का नेतृत्व सचिव स्तर का वरिष्ठ अधिकारी करेगा और इसमें केन्द्र व राज्यों के चार तकनीकी सदस्य होंगे।
3. मुनाफाखोरी के खिलाफ उपायों के बारे में पहले से ही अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इनके तहत मुनाफाखोरी के खिलाफ उपायों को शुरू करने के लिए आवेदनों की स्थायी समिति द्वारा जांच की जाएगी, लेकिन यदि आवेदन स्थानीय मामले से जुड़ा है जिसमें व्यवसाय केवल एक राज्य में है, इसकी पहले राज्य स्तर की स्क्रीनिंग समिति जांच करेगी।
4. स्थायी समिति को अधिकार है कि जिन मामलों में विस्तृत जांच की आवश्यकता है उन्हें सीबीईसी के सेफगार्ड महानिदेशक के पास भेज दिया जाए।

भारत-अमेरिका के बीच नहीं लागू हो सका है LEMOA

भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ी सैन्य सहमति के तौर पर प्रचारित LEMOA पर साइन हुए करीब एक साल होने वाले हैं, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका है। कई मायनों में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास मालाबार इस सहमति के बिना ही संपन्न हो गया है। LEMOA यानी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेण्डम ऑफ अग्रीमेंट। भारत में करीब एक दशक तक चली बहस के बाद पिछले साल अगस्त में यह सहमति हुई थी।

क्या है

1. इसके तहत युद्ध अभ्यास, ट्रेनिंग या आपदा राहत के मामले में एक-दूसरे की सेनाओं को लॉजिस्टिक सपोर्ट, सप्लाई और सर्विस मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। खासतौर से फ्यूल सप्लाई और रिपेयर के लिए बिना बाधा के सुविधाएं मिल सकती हैं।
2. सहमति के बाद इसके जल्द लागू होने की बात की गई थी, लेकिन एक-दूसरे को भुगतान कैसे हो, इस पर बात अटक गई। मसलन अगर भारत का विमान अमेरिकी बेस से फ्यूल ले या अमेरिकी सैनिकों को भारतीय बेस से भोजन मुहैया कराया जाए तो भुगतान किस मुद्रा में होगा और इसकी अकाउंटिंग किस तरह से होगी, भारत में इस मसले को नहीं सुलझाया जा सका था।
3. भारत, अमेरिका और जापान के बीच 7 से 17 जुलाई के बीच बंगाल की खाड़ी में मालाबार अभ्यास चला। इस दौरान भी संधि पर अमल नहीं दिखा। समझा जा रहा था कि मालाबार अभ्यास के दौरान अमेरिका से भारत आए जहाज को फ्यूल और दूसरी सप्लाई इसी समझौते के तहत मिल जाएंगे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अभ्यास के दौरान सहमति ऑपरेशनल नहीं थी। वैसे भारत सपोर्ट की हर डिमांड को पूरा करने के लिए सहमति के तहत बाध्य नहीं है।

सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में संशोधन को स्वीकृति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने सोवरन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) स्कीम को और अधिक उद्देश्य पूर्ण बनाने के लिए इसके दिशा निर्देशों में संशोधन की अनुमति दे दी है।

स्कीम में दो प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं:

1. स्कीम को अधिक आकर्षक बनाने, लक्ष्य के अनुसार वित्तीय साधन जुटाने, सोने के आयात से उत्पन्न आर्थिक दबावों को कम करने तथा चालू खाता घाटा कम करने के लिए इसकी विशेषताओं में बदलाव किया गया है।
2. विभिन्न ब्याज दरों और जोखिम प्रतिरक्षा/चुकता वाले विभिन्न एसजीबी डिजाइन करने एवं शुरू करने के लिए वित्त मंत्रालय को लचीलापन दिया गया है ,जो विभिन्न श्रेणी के निवेशकों को निवेश का विकल्प देगा।
3. वित्त मंत्रालय (जारी करने वाला) को वित्त मंत्री की स्वीकृति से स्कीम की विशेषताओं में संशोधन/ जुड़ाव करने की शक्ति प्रदान की गई है ताकि एक विशेष भाग की विशेषताओं को अंतिम रूप देने और इसकी अधिसूचना के बीच समय-अंतराल को कम किया जा सके।
4. ऐसा लचीलापन नए निवेश उत्पादों के साथ स्पर्धा से कारगर रूप से निपटने में सहायक होगा और इससे गतिशील और उतार चढ़ाव वाले बाजार, वृहत आर्थिक स्थिति और स्वर्ण मूल्य जैसी अन्य स्थितियों से निपटा जा सकेगा।

स्कीम में निम्नलिखित विशेष परिवर्तनों को मंजूरी दी गई है

1. निवेश की सीमा व्यक्तियों के लिए प्रतिवर्ष चार किलोग्राम, हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) तथा न्यासों तथा समय-समय पर सरकार द्वारा सूचित अस्तित्वों के लिए 20 किलोग्राम बढ़ा दी गई है।
2. सीमा की गणना वित्तीय वर्ष के आधार पर की जाएगी और इसमें अनुषंगी बाजार में कारोबार के दौरान खरीदे गए सोवरन स्वर्ण बॉन्ड शामिल होंगे।
3. निवेश सीमा में बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के जमानती हिस्से शामिल नहीं होंगे।
4. सोवरन स्वर्ण बॉन्ड मांग के आधार पर उपलब्ध होंगे। एनएसई, बीएसी, बैंकों तथा डाक विभाग की सलाह के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा मांग के आधार पर उत्पाद की विशेषताएं तय की जाएंगी।
5. सोवरन स्वर्ण बॉन्ड की तरलता और कारोबारी सक्षमता में सुधार के लिए उचित बाजारोन्मुखी पहल किए जाएंगे। वाणिज्यिक बैंक तथा एमएमटीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कोई कम्पनी या सरकार द्वारा निर्धारित कोई कम्पनी बाजार निर्माता होगी।

इरडा का बीमा कंपनियों को आदेश

बीमा राशि जिस पर दस साल से दावा नहीं किया गया है, उसे अगले साल एक मार्च तक कंपनियों को एक फंड में जमा कराना होगा। यह फंड वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। बीमा नियामक इरडा ने कंपनियों को यह निर्देश दिया है। इरडा के मुताबिक, 30 सितंबर, 2017 तक दस साल की अवधि से ज्यादा समय से अगर पॉलिसीधारक की बीमा राशि पर दावा नहीं किया गया है तो कंपनियां उसे वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ) में ट्रांसफर करें। नियामक ने बीमा कंपनियों को वित्तीय सेवा विभाग से संपर्क करने के लिए कहा है। विभाग से उन्हें ऐसे खातों का विवरण प्राप्त करने के साथ उस निर्धारित प्रारूप को लेना है जिसमें दावा नहीं की गई राशि को जमा करना है।

क्या है सीनियर सिटिजन वेलफेयर फंड:

1. केंद्र सरकार वित्त कानून के तहत वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष कानून, 2015 लाई थी। यह सभी छोटी बचत योजनाओं, कर्मचारी भविष्य निधि, बीमा कंपनियों और बैंकों के खातों के खातों से अनक्लेमेट अमाउंट को ट्रांसफर करना अनिवार्य करता है।
2. इस निधि की स्थापना वरिष्ठ नागरिकों के हेतु कल्याणकारी कार्यों जैसे कि वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, ओल्ड एज होम और एक्ट में निर्दिष्ट अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी।

3. सीनियर सिटिजन वेलफेयर फंड (एससीडब्ल्यूएफ) केंद्र सरकार का एक पब्लिक अकाउंट होगा जिस पर ब्याज भी दिया जाएगा। इस खाते में जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज दर का निर्धारण वित्त मंत्रालय की ओर से निर्धारित और अधिसूचित की जाएगी।
4. लाइफ इश्योरेंस सेक्टर में अनक्लेम्ड अमाउंट दोगुना होकर 10,527 करोड़ हो गया है जो कि 31 मार्च 2015 से 31 मार्च 2016 तक 5,440 करोड़ रहा था। लिमिटेशन एक्ट-1963 के अंतर्गत तीन साल के भीतर पॉलिसी होल्डर के क्लेम को निपटाने की सुविधा प्रदान करता है।

देश में कार्ड से ट्रांजेक्शन बढ़ा

देशभर में नोटबंदी लागू होने के बाद डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया गया था। इन प्रयासों के चलते छह महीनों में डिजिटल ट्रांजेक्शन में करीब 23 फीसद तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यह जानकारी नोटबंदी और डिजिटल इकोनॉमी पर बनी संसदीय कमेटी के समक्ष एक सरकारी अधिकारी ने दी है। इस संसदीय कमेटी के समक्ष विभिन्न सरकारी विभागों के कई अधिकारी पेश हुए हैं।

क्या है

1. सरकारी अधिकारी की ओर से संसदीय कमेटी को दी गई दी प्रेजेंटेशन में बताया गया है कि बीते वर्ष नवंबर के दौरान देश में कुल 2.24 करोड़ डिजिटल लेनदेन हुए थे। यह मई 2017 में बढ़कर 2.75 करोड़ तक पहुंच गए हैं।
2. डिजिटल ट्रांजेक्शन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए ट्रांजेक्शन में दर्ज की गई है। छह महीनों में यूपीआई के जरिए डिजिटल ट्रांजेक्शन करीब 30 गुना बढ़ा है।
3. नवंबर 2016 में यूपीआई के जरिए रोजाना केवल दस लाख लेनदेन हो रहे थे। यह मई 2017 में बढ़कर करोड़ के स्तर पर पहुंच गए हैं।
4. दूसरी ओर इस दौरान इमिडिएट पेमेंट सिस्टम (आईएमपीएस) के जरिए हुए ट्रांजेक्शन में भी करीब दोगुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नवंबर 2016 में आईएमपीएस के जरिए 12 लाख लेनदेन होते थे। यह मई, 2017 में बढ़कर 22 लाख तक पहुंच गए हैं।
5. इस दौरान क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए हुए लेनदेन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। नवंबर 2016 से मई 2017 के दौरान कार्ड के जरिए लेन-देन केवल सात फीसद ही बढ़ा है।
6. नवंबर 2016 में कार्ड के जरिए करीब 68 लाख लेनदेन दर्ज किए गए थे जो मई में बढ़कर केवल 73 लाख तक पहुंच पाए हैं।

विज्ञान एवं तकनीकी

2030 तक मंगल पर बस्ती बसाना संभव नहीं

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कबूल किया है कि मंगल ग्रह पर 2030 के दशक में मानव को भेजने का सपना पूरा करना संभव नहीं है। मंगल ग्रह पर बस्ती बसाना लंबे समय से मानव का सपना रहा है। नासा ने खुद एलान किया था कि वह 2030 के दशक में लाल ग्रह पर मनुष्यों को भेजेगी। लेकिन पैसे की कमी इन अंतरिक्ष योजनाओं की राह में एक बड़ी बाधा है। नासा के अंतरिक्ष के मानव अन्वेषण कार्यक्रम के प्रमुख विलियम गेरस्टेनमैर ने बताया कि मंगल अभियान के मौजूदा बजट से एजेंसी इस ग्रह के लिए मानवयुक्त अभियान को बढ़ावा देने का खर्च वहन नहीं कर सकती। गेरस्टेनमैर ने कहा, इस स्थिति में मैं 2030 के दशक में मंगल ग्रह पर मनुष्य के पहुंचने की कोई तारीख नहीं तय कर सकता।

क्या है

1. नासा ने इस परियोजना को अपने अन्वेषण कार्यक्रम की उच्च प्राथमिकता बनाया है। वह पहले से ही संभावित अन्वेषण क्षेत्रों का अध्ययन कर रही है, जिनसे संभावित निवासियों को संसाधन को मुहैया हो सकेगा। एजेंसी मंगल पर कई मानवरहित खोजी यान उतार चुकी है। इनमें क्यूरिऑसिटी रोवर हाल

- का है, जिसे अगस्त 2012 में मंगल पर उतारा गया। इस अभियान की लागत 2.5 अरब डॉलर आंकी गई थी।
2. गेरस्टेनमैर के मुताबिक, मंगल के लिए मानवयुक्त अभियान रोवर के मुकाबले 20 गुना वजनी होगा। इसका मतलब हुआ कि इसकी लागत रोवर से 20 गुना अधिक होगी।
 3. अमेरिका ने नासा को वित्त वर्ष 2017 के लिए 19.5 अरब डॉलर का बजट आवंटित किया है। लेकिन गेरस्टेनमैर ने कहा, बजट के स्तर पर यह मोटे तौर पर दो फीसदी बढ़त है।
 4. हमारे पास मंगल ग्रह के लिए सतह प्रणाली उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मंगल के दायरे में प्रवेश करना और उस पर उतरना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है।
 5. मंगल पर मानव को भेजने पर अगले ढाई-तीन दशक में 100 अरब डॉलर से लेकर एक लाख करोड़ डॉलर तक का खर्च आ सकता है। कुछ निजी संगठन भी अपने मंगल मिशन को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन संभावित खर्च को लेकर वे और कंजूसी बरत रहे हैं।
 6. मार्स वन नामक एक डच-स्विस संगठन का महज छह अरब डॉलर की लागत से चार लोगों को मंगल पर भेजने का सपना देख रही है। जबकि स्पेसएक्स के संस्थापक एलोन मस्क ने 2016 में एक यात्री को भेजने की संभावित लागत 10 अरब डॉलर बताई थी।

पृथ्वी को 'प्लास्टिक प्लेनेट' में बदलने की तैयारी

एक अध्ययन के अनुसार, पृथ्वी पर जमा हो रहे प्लास्टिक के अंबार से जल्द ही पृथ्वी को प्लास्टिक प्लेनेट के तौर पर देखा जा सकता है। अध्ययन में बताया गया है कि वर्ष 1950 से अब तक मानवों ने 8.3 बिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन किया है और इसमें से अधिकतर प्राकृतिक वातावरण या खाली स्थानों में भरे पड़े हैं। अमेरिका में जॉर्जिया यूनिवर्सिटी (यूजीए) के रिसर्चर्स ने अध्ययन किया और पाया कि 2015 तक मनुष्यों ने 8.3 मीट्रिक टन प्लास्टिक पैदा किया था जिसमें से 6.3 बिलियन टन बर्बाद हो गए थे। कुल कचरे में से 9 फीसद कचरे का पुनःचक्रण किया गया, 12 फीसद जलाया गया और 79 फीसद गड्ढों या प्राकृतिक वातावरण में फैंल गए। यदि वर्तमान ट्रेंड आगे भी जारी रहा तो 2050 तक प्राकृतिक वातावरण में करीब 12 बिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक फैंल जाएगा।

क्या है

1. यूजीए की इंजीनियरिंग की असोसिएट प्रोफेसर, जेन्ना जैम्बेक ने बताया, 'अधिकतर प्लास्टिक अर्थपूर्ण तरीके से बायोडिग्रेड नहीं होते इसलिए मनुष्यों द्वारा उत्पन्न किए जा रहे प्लास्टिक कचरे सैकड़ों हजारों साल तक हमारे साथ रहते हैं।
2. अध्ययन से पता चलता है कि 'हमें वस्तुओं के उपयोग व कचरा प्रबंधन पर गंभीरता पूर्वक सोचने की जरूरत है।' व्यापक तौर पर प्लास्टिक उत्पादन का आंकड़ा 1950 के 2 मिलियन मीट्रिक टन से 2015 के 400 मिलियन मीट्रिक टन पर पहुंच गया। यह अध्ययन जर्नल साइंस एडवांसेज में प्रकाशित हुआ।
3. कुछ अपवाद सामग्रियां हैं जिनका उपयोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में होता है जैसे स्टील और सीमेंट वहीं प्लास्टिक का उपयोग पैकेजिंग में किया जाता है। इनमें अधिकतर वैसे होते हैं जो एक बार के उपयोग के बाद फेंक दिए जाते हैं।
4. 1950 से 2015 तक में प्लास्टिक के कुल उत्पादन का करीब आधा हिस्सा केवल अंतिम 13 सालों के दौरान हुआ है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चीन आगे

चीन जिस तरह से तेजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विकास कर रहा है उससे अमेरिका समेत दुनिया के तमाम दिग्गज देश चिंतित हैं। क्योंकि माना जा रहा है कि चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर सकता है। एक रिपोर्ट अनुसार चीन बड़े पैमाने पर कम्प्यूटरों का जखीरा तैयार कर रहा है। हजारों इंजीनियर मशीनों में कोडिंग करने जुटे हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में अमेरिका नाम सबसे आगे आता है लेकिन आने वाले कुछ ही सालों में चीन दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़ देगा।

क्या है

1. चीन बहुत तेजी के साथ क्लाउड कम्प्यूटिंग की क्षमता बढ़ा रहा है जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर शोध किया जा सके।
2. पिछले हफ्ते ही चीन ने एक महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया है। योजना के अनुसार अगले 10 सालों में चीन एआई टेक्नोलॉजी में तेज गति से विकास करने लगेगा। इतना ही 2030 तक वह एआई क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर दुनिया का बेताज बादशाह बन जाएगा।
3. एआई में पैटेंट के आवेदन चीन में 2010 से 2014 के बीच में तीन गुना हो गए हैं। अभी में चीन में 700 मिलियन यानी 70 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं। यह संख्या दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है।
4. चीन की कई कंपनियां भी अपने यूजर्स को बेस्ट टेक्नोलॉजी का अनुभव कराने के लिए प्रयासरत हैं। चीन योजना 2030 तक एआई में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने की है।
5. चीन की योजना भारत के लिए भी चिंता का विषय है क्योंकि तकनीकी रूप में बहुत आगे बढ़ने से चीन भारत की साइबर सिव्यूरिटी के खतरा बन सकता है।

धरती के बेहद पास से गुजरेगा क्षुद्रग्रह

वैज्ञानिकों ने कहा कि एक छोटे आकार का क्षुद्रग्रह हमारी धरती के बेहद करीब से गुजर सकता है। इससे नासा को आब्जर्वेटरी नेटवर्क और ग्रहों की सुरक्षा प्रणाली को परखने का मौका मिलेगा। 2012 टीसी4 नामक क्षुद्रग्रह 12 अक्टूबर को धरती के पास से सुरक्षित गुजरेगा। इस नन्हे ग्रह का आकार महज 10 से 30 मीटर होने का अनुमान है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक यह सटीक अनुमान नहीं लगा सके हैं कि यह धरती के कितना करीब से होकर गुजरेगा। लेकिन उन्हें इस बात का यकीन है कि यह धरती की सतह से 6,800 किलोमीटर से ज्यादा करीब नहीं आएगा।

क्या है

1. यह नन्हा क्षुद्रग्रह साल 2012 से टेलीस्कोप के दायरे से परे रहा है। नासा मुख्यालय में टीसी4 आब्जर्वेशन अभियान के प्रमुख माइकल केली ने कहा, वैज्ञानिक हमेशा से यह जानने के प्रयास में रहते हैं कि कब कोई क्षुद्रग्रह करीब पहुंचेगा और सुरक्षित धरती के पास से गुजरेगा।
2. इससे उन्हें नया कुछ जानने और आंकड़े जुटाने के लिए तैयारी करने में मदद मिल सकती है।
3. क्षुद्रग्रह 2012 टीसी4 एक अंतरिक्ष चट्टान से थोड़ा बड़ा हो सकता है। इस आकार का एक चट्टान फरवरी 2013 में रूस के चेल्याबिंस्क के पास धरती के वायुमंडल से टकराया था।
4. यह क्षुद्रग्रह पिछले पांच साल से इतना दूर और इतना धूमिल था कि इसे देखा नहीं जा सका था।

जमीन पर हुई थी प्रारंभिक जीवन की शुरुआत

धरती पर प्रारंभिक जीवन को लेकर फिर नई बहस छिड़ गई है। नए शोध में दावा किया गया है कि धरती पर 58 करोड़ साल पहले सूक्ष्मजीव समुद्र नहीं बल्कि जमीन पर पैदा हुए थे। यह शोध स्ट्रोमेटोलाइट मॉडल पर आधारित है। स्ट्रोमेटोलाइट बहुस्तरीय खनिज संरचना है। इनका आकार गोल्फ बॉल से लेकर विशाल गुब्बारे तक का होता है।

क्या है

1. ये धरती पर 3.5 अरब साल पहले जीवित जीवों के प्राचीन प्रमाण को दर्शाते हैं।
2. कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और सिडनी की न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की टीम ने दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के पिलबरा क्षेत्र में इनका बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने उन साक्ष्यों की तलाश की जिससे यह पता चल सके कि प्राचीन सूक्ष्मजीवों ने किस तरह प्रचुर मात्रा में स्ट्रोमेटोलाइट का निर्माण किया था। इन स्ट्रोमेटोलाइट की खोज 1970 के आसपास की गई थी।
3. कई वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की शुरुआत समुद्र में हुई थी। उनकी नजर में इन खनिजों की उत्पत्ति छिछले और खारे समुद्री पानी में उसी तरह हुई थी जिस तरह विश्व विरासत सूची में शामिल शार्क बे इलाके में स्ट्रोमेटोलाइट की हुई थी।

4. जबकि इसके विपरित न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता तारा जोकि ने यह पता लगाया कि स्ट्रोमेटोलाइट की उत्पत्ति खारे पानी में नहीं हुई थी। इनका निर्माण यलोस्टोन में गर्म मौसम के हालात में हुआ था।

टाइटन के मीथेन सागर में हो सकती है जीवन की संभावना

वैज्ञानिकों ने पहली बार टाइटन पर एक्रिलोनाइट्राइल नामक एक सूक्ष्म कण की मौजूदगी का पता लगाया है जो वहां जीवन का आधार हो सकता है। टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है जिस पर मीथेन का सागर मौजूद है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है।

क्या है

1. कोरनेल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कहा कि इस खोज ने उन्हें एक बिल्कुल अपरिचित वातावरण में जीवन की खोज के करीब ला दिया है।
2. शोधकर्ता जोनाथन लुनाइन ने कहा, शोधकर्ताओं ने निर्णायक तौर पर टाइटन पर इस सूक्ष्म कण को खोज निकाला है। यह ऐसी नमूना कोशिका के लिए आदर्श कण हो सकता है जो तरल मीथेन में टिक सकती है। यह खोज टाइटन के मीथेन सागर में जीवन के एक अपरिचित रूप की संभावित मौजूदगी को समझने की दिशा में अग्रणी कदम है।
3. शनि के चंद्रमा, एंसेलाडस पर पृथ्वी के समान जीवन की संभावना जताई जाती रही है। इसका मतलब ऐसे जीवन से है जो तरल जल पर आधारित होगा।
4. लेकिन टाइटन ऐसा उपग्रह है जहां जीवन का कोई दूसरा ही रूप हो सकता है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है। वहां तरल मीथेन है।

तारों से बने हैं हम इंसान

अगर यह कहा जाए कि हम इंसान तारों से बने हैं, तो यह गलत नहीं होगा। खगोलशास्त्रियों का कहना है कि जिन अणुओं से हमारा शरीर बना है, उनमें से आधे से ज्यादा ऐटम्स ऐसे हैं जिनका जन्म हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के पार हुआ। तारों के विस्फोट के बाद अंतरिक्ष में चलने वाली हवाओं की मदद से ये कण हमारे सौर मंडल में आए। अंतरिक्ष में चलने वाली ये हवाएं जीवन के निर्माण में काफी मददगार साबित होती हैं। इनकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। खगोलशास्त्रियों का कहना है कि ये हवाएं करीब 10 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी तय कर सकती हैं। मालूम हो कि एक प्रकाश वर्ष 9 खरब किलोमीटर के बराबर होता है।

क्या है

1. 'द गार्डियन' अखबार ने एक ताजा खगोलीय शोध के नतीजों के हवाले से यह जानकारी दी है। खगोलशास्त्रियों का यह निष्कर्ष हो सकता है कि आपको नाटकीय लगे, लेकिन है यह बिल्कुल सच। आकाशगंगाएं अनंत काल तक बहुत विशाल मात्रा में पदार्थों को अवशोषित करती रहती हैं। जब तारों की उम्र पूरी हो जाती है तो वे फट जाते हैं।
2. इस विस्फोट के कारण उनसे निकले पदार्थ पड़ोसी आकाशगंगाओं द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। सुपरनोवा (अधिनोवा उन तारों को कहा जाता है, जो विस्फोट होने के कारण चमकते हैं) विस्फोट के कारण खरबों टन अणु अंतरिक्ष में फैल जाते हैं।
3. विस्फोट की तीव्रता के कारण ये कण इतनी जोरदार गति के कारण निकलते हैं कि उनके आकाशगंगा का गुरुत्वाकर्षण बल भी उन्हें खींचकर रोक नहीं पाता। ये कण विशाल बादलों का रूप लेकर पड़ोसी तारों, आकाशगंगाओं और सौर मंडलों में फैल जाते हैं। इन बादलों की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि ये एक सेकंड में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पार कर लेते हैं।
4. खगोलशास्त्रियों को लंबे समय से पता था कि तारों के अंदर बने पदार्थ और कण एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा तक पहुंच सकते हैं। अब इस ताजा शोध से पहली बार यह पता चला है कि हमारी आकाशगंगा और इसके बराबर आकार वाली आकाशगंगाओं के आधे से ज्यादा पदार्थ किसी अन्य आकाशगंगा से आए हो सकते हैं।

5. इस तरह आकाशगंगाओं में फैलने वाले हाइड्रोजन और हीलियम से नए तारों की रचना होती है, वहीं भारी पदार्थ जो कि खुद तारों में पैदा होकर विस्फोट के बाद फैल जाते हैं वे धूमकेतु, ऐस्टरॉइड, ग्रह और बाकी जीवन के निर्माण में कच्चा माल साबित होते हैं।
6. नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एक खगोलशास्त्री डेनियल अलजार ने कहा, 'इस अथाह ब्रह्मांड में अपनी जगह पता करने में विज्ञान काफी मदद करता है। हम इस आकाशगंगा को अपना समझते हैं, लेकिन असल में हम खुद भी तो यहां के नहीं। देखा जाए तो हम यहां आए हैं, यहां बसे हैं।'
7. खरबों साल पहले आकाशगंगाएं किस तरह अस्तित्व में आईं, इसे समझने के लिए शोधकर्ताओं ने **सुपरकंप्यूटर पर सिमुलेशन तैयार किया**। उन्होंने देखा कि छोटी-छोटी आकाशगंगाओं में जैसे ही तारों के अंदर विस्फोट होता है, तो उस ब्लास्ट के कारण बनने वाले बादल अपने अगल-बगल की बड़ी आकाशगंगाओं तक पहुंच जाते हैं।
8. मिल्की वे की बात करें, तो **हर साल दूसरी आकाशगंगाओं से यहां इतना पदार्थ आ जाता है जो एक सूर्य के बराबर होगा**। वैज्ञानिकों का कहना है कि आकाशगंगाओं में चलने वाली हवा उम्मीद से कहीं ज्यादा पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह लाती-ले जाती है।
9. खगोलीय पिंडों और जीवन के निर्माण में इन हवाओं का योगदान काफी अहम है। ब्रह्मांड के विकास की इस थिअरी पर पहले ज्यादा विचार नहीं किया गया था, लेकिन अब खगोलशास्त्री इसे काफी अहमियत दे रहे हैं।

विविध

वैज्ञानिकों ने पाया है कि **जलरीछ (टार्डीग्रेड) नामक जीव सूर्य के खत्म होने तक जीवित रहेगा**। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि जलरीछ तमाम खगोलीय विनाशों से बच निकलेगा। यह **मानव जाति के मुकाबले कम से कम 10 अरब साल ज्यादा समय तक अपना अस्तित्व कायम रखेगा**। शोधकर्ताओं ने आठ पैरों वाले इस सूक्ष्म जीव को **विश्व का अनश्वर जीव घोषित किया है**।

क्या है

1. शोधकर्ताओं के अनुसार, **जलरीछ पृथ्वी पर जीवन का सबसे जिद्दी और सबसे लचीला रूप है**। इसको देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि एक बार इसका जीवन शुरू होने के बाद इसको नष्ट करना कठिन है। इस तरह यह अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना को जगा देता है। यह बिना भोजन-पानी के अर्से तक जीवित रह सकता है। यह अत्यधिक तापमान में रह सकता है। यह जितनी आसानी से गहरे समुद्र में रह सकता है उतनी ही आसानी से अंतरिक्ष के निर्वात में भी रह सकता है।
2. जलरीछ के रूप में जीवन का अस्तित्व **किसी भी खगोलीय विनाशकारी घटना में बचा रह जाएगा**। उन्होंने अध्ययन में तीन खगोलीय विनाशकारी घटनाओं पर गौर किया। ये घटनाएं हैं किसी बड़े क्षुद्रग्रह का प्रभाव, सुपरनोवा के रूप में किसी तारे में विस्फोट या गामा किरणों की बौछार। शोधकर्ताओं ने कहा, क्षुद्रग्रह की टक्कर जैसी घटना कभी इतनी मजबूत नहीं होगी कि दुनिया के महासागरों को बिल्कुल खौला दे। ऐसे में जलरीछ बचा रह सकता है।

यह जिव

1. 30 साल तक बिना खाए-पीए आराम से रह सकता है।
2. 150 डिग्री सेल्सियस में भी जीवित रह सकता है।
3. 773 में जर्मन जीवविज्ञानी जे. ए. एप्राहिम गोएजे ने खोज की थी।
4. 60 साल तक जीवित रह सकता है और अधिकतम 0.5 मिमी लंबाई।

यूनिसेफ की सद्भावना दूत बनीं लिली सिंह

भारतीय मूल की **कनाडाई युवती लिली सिंह** को दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में आयोजित एक कार्यक्रम में **यूनिसेफ का सद्भावना दूत बनाया गया**। सद्भावना दूत के तौर पर वे अपने

अनोखे डिजिटल मंच पर बच्चों और युवाओं को लाकर उन्हें सशक्त बनाने की कोशिश करेंगी। डिजिटल उपनाम सुपरवुमेन से लोकप्रिय हुई लिली यहां यूनिसेफ द्वारा सहयोग प्राप्त बच्चों व युवाओं से मिलने आई थीं।

क्या है

1. लिली ने कहा कि हर बच्चे तक पहुंचने के लिए आवाज उठाऊंगी। अब तक जिन बच्चों से मिली हूँ वे प्रमाणित कर रहे हैं कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे क्या नहीं कर सकते।
2. **28 वषीय लिली के यू-ट्यूब पर 11 मिलियन फॉलोअर हैं।** भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि डॉ. यास्मीन अली हक ने कहा हम लोग भारत और हर जगह पर लड़कियों के महत्व के बारे में बड़ी चर्चा करते हैं और उस पर काम करते हैं।
3. यूनिसेफ की सद्भावना दूत के तौर पर लिली अपने मंच का प्रयोग बाल अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए करेंगी।

स्मृति इरानी को सूचना एवं प्रसारण का अतिरिक्त कार्यभार

केंद्रीय मंत्री के तौर पर वेंकैया नायडू ने 18 जुलाई को इस्तीफा दे दिया जिसके बाद शहर विकास मंत्रालय का जिम्मा नरेंद्र तोमर व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार स्मृति इरानी को सौंपा गया है। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दिया है।

क्या है

1. स्मृति इरानी के पास पहले से कपड़ा मंत्रालय है। इससे पहले वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मंत्री थीं। वेंकैया नायडू को एनडीए ने उप राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस वजह से उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया।
2. **नायडू के पास इसके अतिरिक्त शहरी विकास मंत्रालय का प्रभार भी था।** नरेंद्र तोमर को इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दरअसल नायडू की उपराष्ट्रपति उम्मीदवारी के साथ ही केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल के जल्द ही विस्तारित होने की संभावना जताई जा रही है।

शिक्षा पर केंग की रिपोर्ट

छह साल पहले शिक्षा के अधिकार कानून का लागू होना भारत में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था। इस कानून के तहत पूरे भारत में हर बच्चे के लिए चौदह वर्षों तक की शिक्षा उसका अधिकार माना गया, लेकिन व्यवस्था की लचरता और निराशाजनक माहौल के चलते इस शिक्षा अधिकार अधिनियम से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले सके। एक जरूरी, सार्थक और परिवर्तन का आधार बनने वाला कानून भी गड़बड़ियों का शिकार बन कर रह गया। इसी बात को पुख्ता करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संसद में पेश ताजा रिपोर्ट, जिसमें आरटीइ को लेकर हो रही गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में सामने आया है कि इसके तहत जो पैसे दिए जाते हैं, वे खर्च ही नहीं हो पाते। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकारें कानून लागू होने के बाद के छह सालों में उपलब्ध कराए गए कुल फंड में से 87,000 करोड़ रुपये का भी इस्तेमाल नहीं कर पाई हैं।

क्या है

1. केंग की यह रिपोर्ट इस बात का भी खुलासा करती है कि कागजों पर पूरी हो रही औपचारिकताओं के बीच न तो पारदर्शिता है और ना ही जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा मिल पा रही है।
2. देश को बदल देने का पुख्ता आधार तैयार करने वाले कानून का यह हाल हमारी बदहाल व्यवस्था की तस्वीर सामने रखता है।
3. भारत में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है। इस कानून को पूरे देश में अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इसमें शिक्षा से जुड़े कई ऐसे पहलुओं को समाहित किया गया जो ना केवल साक्षरता के आंकड़े बढ़ाएं बल्कि बच्चों का संपूर्ण विकास भी करें।
4. दाखिले के समय अनुदान ना लेना, अभिभावकों का साक्षात्कार ना लेना, विकलांग बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए ससम्मान दाखिला देना, आठ साल तक की शिक्षा पूरी करने तक किसी भी बच्चे

को स्कूल से नहीं हटाना, स्कूलों में शिक्षकों और कक्षाओं की पर्याप्त संख्या, लड़कियों और लड़कों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था और बच्चों को मानसिक यातना और शारीरिक दंड ना दिए जाने जैसे नियम शामिल हैं।

5. देश के दूर दराज के इलाकों में भी यह कानून बेहतर ढंग से लागू हो सके इसके लिए इस अधिनियम के तहत, शिकायत निवारण के लिए ग्राम स्तर पर पंचायत, क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर संसाधन केंद्र (सीआरसी), तहसील स्तर पर पंचायत, जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की व्यवस्था भी की गई। यह व्यवस्था जरूरी थी ताकि साक्षरता में पिछड़े और सामाजिक, आर्थिक असमानता का दंश डोल रहे हमारे देश में सभी बच्चे समान रूप से शिक्षा पा सकें।
6. गरीब परिवारों और संसाधनहीन पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को शिक्षित बनाने ले लिए इस कानून में गंभीरता से विचार किया था। क्योंकि साक्षरता के आंकड़ों में पीछे होना हमारी बड़ी समस्याओं में से एक रहा है।
7. गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74 फीसद है। यूनेस्को के अनुसार भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अनपढ़ों का देश है। कुछ समय पहले राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) की ओर से आए आंकड़े भी बताते हैं कि देश के शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर जहां 86 फीसद थी वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 71 फीसद तक ही सीमित रहा।
8. यूनेस्को के मुताबिक दुनिया भर में करीब 78 करोड़ लोग अशिक्षित हैं। अशिक्षितों के इस आंकड़े में लोगों का 75 फीसद जिन 10 देशों में हैं, उनमें भारत भी शामिल है।

डिजिटल इवोल्यूशन इंडेक्स 2017

डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत मजबूती से उभरा है और उसने इस मामले में भारी संभावनाएं दर्शाई हैं। डिजिटल इवोल्यूशन इंडेक्स 2017 के अनुसार भारत की गिनती उन 60 देशों की ब्रेक आउट श्रेणी में हुई है, जिसमें किसी देश का डिजिटल विकास का स्तर काफी नीचे होने के बावजूद विकास की व्यापक संभावनाएं हैं और इसके कारण निवेशकों के लिए आकर्षक बाजार बनकर उभरे हैं।

क्या है

1. अमेरिका की टुफ्ट्स यूनिवर्सिटी के फ्लेचर स्कूल ने मास्टर कार्ड के सहयोग से डिजिटल इवोल्यूशन इंडेक्स 2017 तैयार किया है।
2. इस इंडेक्स में तमाम देशों में डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए हुई प्रगति और आम लोगों को इससे जोड़ने के प्रयासों पर व्यापक अध्ययन किया गया है।
3. मास्टर कार्ड के अनुसार भारत में नोटबंदी के फैसले के कारण बने माहौल ने डिजिटल पेमेंट की दिशा में खासी बढ़त के लिए आधार तैयार किया। आज भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग दैनिक जीवन में डिजिटल पेमेंट को अपना रहे हैं। इसके कारण तेज प्रगति दर्ज की गई है।
4. मास्टर कार्ड के कंट्री कॉरपोरेट ऑफीसर व प्रेसीडेंट (साउथ एशिया) पौरुष सिंह ने कहा कि भारतीय बाजार में नई कंपनियां आ रही हैं और वैकल्पिक भुगतान के तमाम समाधान सामने आ रहे हैं। इससे तेज विकास के लिए माहौल बन रहा है।
5. आज दुनिया में करीब आधी आबादी ऑनलाइन है, स्टडी में 60 देशों में अच्छी प्रगति दिखाई दी है। इन देशों में डिजिटल आर्थिक विकास के लिए प्रतिस्पर्धा का माहौल है और काफी संभावनाएं हैं। इंडेक्स में सप्लाई, उपभोक्ता मांग, संस्थागत माहौल और इनोवेशन पर देशों का आंकलन किया गया है।
6. नीति आयोग ने कहा है कि डिजिटल पेमेंट का विस्तार होने के कारण अगले तीन साल में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सर्विस मार्केट 14 अरब डॉलर (91000 करोड़ रुपये) का हो जाएगा।
7. इस समय 600 से ज्यादा स्टार्टअप कर्ज वितरण, भुगतान, बीमा और ट्रेडिंग में लगे हैं। इस समय इस सेक्टर का कुल बाजार करीब आठ अरब डॉलर का है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद डिजिटल

पेमेंट का तेजी से विकास हुआ है। वर्ष 2016-17 में डिजिटल पेमेंट बीते वर्ष के मुकाबले 55 फीसद बढ़ गया। पिछले पांच वर्षों में औसत विकास दर 28 फीसद रही।

8. सीआइआई के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस दौरान डेबिट कार्ड 104 फीसद, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट 163 फीसद और पीओएस यानी स्वाइप मशीनों का इस्तेमाल 83 फीसद बढ़ गया। उन्होंने कहा कि नकदी से लेनदेन काफी महंगा पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक को हर साल करेंसी प्रचलन पर करीब 21000 करोड़ रुपये का खर्च करना होता है।

सुब्रमण्यम बने टीम इंडिया के मैनेजर

तमिलनाडु के बाएं हाथ के पूर्व स्पिनर सुनील सुब्रमण्यम को एक साल के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का प्रशासनिक मैनेजर नियुक्त किया गया। भारत के शीर्ष ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के बचपन के कोच के रूप में पहचान पाने वाले सुब्रमण्यम 3 अगस्त से कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से पूर्व टीम के साथ जुड़ेंगे।

क्या है

1. बीसीसीआई ने बताया कि, 'उन्हें एक साल के लिए अनुबंधित किया गया है' और दूसरा टेस्ट शुरू होने से पहले श्रीलंका में टीम से जुड़ेंगे।
2. असम और तमिलनाडु की ओर से 74 मैचों में सुब्रमण्यम ने 285 विकेट चटकाने के अलावा 1096 रन भी बनाए। बीसीसीआई ने हालांकि फिलहाल भारत ए और अंडर 19 टीम के लिए मैनेजर नियुक्त नहीं किया है।
3. एक समय अरमान मलिक को भारत का मैनेजर नियुक्त करने की दौड़ में बताया जा रहा था और भारत ए अंडर 19 मैनेजर के लिए विकल्प प्रकाश भट और शंकर सैनी के बीच था।
4. भारत ए और अंडर 19 टीम को सीनियर टीम जितनी श्रंखला नहीं खेलनी इसलिए पूर्णकालिक मैनेजर नियुक्त करने की जरूरत नहीं है। जरूरत होने पर बीसीसीआई अपने प्रशासन में से किसी को यह जिम्मेदारी सौंप सकता है।

महिलाओं के लिए हुए काम के आधार पर होगी रेटिंग

देश में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए प्रस्तावित नई राष्ट्रीय महिला नीति पर समुचित अमल सुनिश्चित करने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए नीति के मसौदे को मंजूरी देने वाले मंत्रियों के समूह ने मसौदे में ही इसका प्रावधान कर दिया है। महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे मानकों पर लक्ष्य तय किये जाएंगे। इन मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का आकलन होगा और उनकी सालाना रेटिंग होगी।

क्या है

1. इन मानकों के लिए तय लक्ष्यों को प्राप्त करना राज्यों के गवर्नेंस को दर्शाएगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि संकेतकों पर कैसा काम कर रहे हैं यह उनका सालाना प्रदर्शन तय करेगा। मसौदे में इसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार करने की बात भी कही गई है।
2. इस एक्शन प्लान के तहत राज्यों की उपलब्धि क्या रही या वे इस पर कैसा काम कर रहे हैं इसकी निगरानी रखने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति गठित करने का भी प्रस्ताव है।
3. इसके लिए ऐसा तंत्र विकसित किया जाएगा जिसके साथ राज्य और अन्य स्तरों पर समन्वय बनाया जा सके।
4. प्रत्येक राज्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य महिला उच्चाधिकार समिति के गठन का भी प्रावधान नीति के मसौदे में किया गया है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला महिला उच्चाधिकार प्राप्त टास्कफोर्स भी गठित की जाएगी।

5. सरकार को इस तरह की नीति बनानी होगी जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुप की मुहिम को देश भर में प्रोत्साहन दिया जा सके। मसौदे में माना गया है कि नई राष्ट्रीय महिला नीति के ढांचे को जमीन पर उतारने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय प्रशासन के स्तर पर एक व्यापक और प्रभावी रणनीति की आवश्यकता होगी।
6. इसके तहत महिलाओं के लिए प्राथमिकता वाले प्रत्येक क्षेत्र के लिए सालाना कार्ययोजना तैयार करने की जरूरत होगी जिन्हें वित्त वर्ष के अंतर्गत ही प्राप्त करना होगा।

बड़ा ऐतिहासिक है आज का दिन

चांद के पार जाने की बात भले ही हिन्दी फिल्मों के गानों में होती रही हो लेकिन चांद तक जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आज तक के मानव इतिहास में ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है। आज से ठीक 48 साल पहले नील आर्मस्ट्रॉंग नाम के अमेरिकी अंतरिक्षयात्री ने यह कारनामा किया था। 20 जुलाई 1969 को नील ने पहली बार चांद की जमीन पर कदम रखे और मून वॉक किया था।

वो ऐतिहासिक दिन...

1. 16 जुलाई की सुबह नील आर्मस्ट्रॉंग व अन्य अंतरिक्ष यात्री अपोलो 11 में सवार हुए। सैटर्न-ट ने कैंनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी और सिर्फ 12 मिनट बाद अपोलो 11 धरती की कक्षा में पहुंच चुके थे।
2. इसके तीन दिन बाद आर्मस्ट्रॉंग और एड्रिन चांद की धरती पर थे। दोनों अंतरिक्षयात्रियों ने करीब 2.5 घंटे चांद की जमीन पर बिताए। इस ऐतिहासिक दिन को 3.5 करोड़ लोगों ने टीवी पर देखा और रेडियो पर सुना भी।
3. चांद की जमीन पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉंग ने कहा था, यह मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है और मानव जाति के लिए विशाल छलांग है। उन्होंने कहा, हम पूरी मानव सभ्यता की तरफ से चांद पर कदम रख रहे हैं। आज 48 साल हो चुके हैं, नील और एड्रिन के अलावा आज तक कोई अन्य इंसान चांद पर नहीं पहुंच सका है।

एड्स से होने वाली मृत्यु दर आधी: UN

संयुक्त राष्ट्र ने 20 जुलाई को कहा कि 2005 के बाद से एड्स के कारण होने वाली मृत्युदर अब आधी हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने महामारी पर अपनी नवीनतम वैश्विक रिपोर्ट में ये बात कही है। रिपोर्ट के अनुसार, 1980 के दशक से दुनिया भर में अब तक एड्स के कारण 35 लाख लोगों की मौत हो गई है। नई परिणाम अफ्रीका के लिए विशेष रूप से उत्साहजनक संकेत हैं जो काफी समय से इस बीमारी से तबाह महाद्वीप है। पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका, में 2010 से अब तक करीब 30 प्रतिशत तक नए एचआईवी संक्रमण में कमी की सूचना है।

क्या है

1. एचआईवी परीक्षण, उपचार और रोकथाम के बाद 2005 के बाद मृत्युदर में आधी गिरावट आई है। परिणामस्वरूप, बुरी तरह प्रभावित देशों में लोगों के जीवनकाल सीमा में भी वृद्धि दर्ज की गई। उदाहरण के तौर पर, पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में, औसत जीवन सीमा 2006 से 2016 तक लगभग 10 वर्षों की वृद्धि हुई।
2. अब धीरे-धीरे स्वास्थ्य परिणाम सुधर रहे हैं और देश मजबूत हो रहे हैं। रिपोर्ट ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा, हालांकि सभी क्षेत्रों में प्रगति नहीं हो रही है मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में, एड्स से संबंधित मौतों में क्रमशः 48 प्रतिशत और 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन तक उपचार नहीं पहुंचने के कारण ये मौतें हुई हैं।
3. रिपोर्ट के अनुसार, अल्जीरिया में 2010 में 24 प्रतिशत से बढ़कर 2016 में एचआईवी के उपचार में 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मॉरॉको में 2010 में 16 प्रतिशत से बढ़कर 2016 में 48 प्रतिशत हो चुका था।
4. बेलारूस में 2010 में 29 प्रतिशत से बढ़कर 45 प्रतिशत तक हो गया था। हम 2015 के 15 लाख लोगों के उपचार के लक्ष्य को 2020 तक 30 लाख के वैश्विक लक्ष्य रखा है।

पूर्व इसरो चीफ यू. आर. राव का निधन

भारत के पहले सेटेलाइट आर्यभट्ट की उड़ान की कल्पना को साकार करने वाले महान वैज्ञानिक यूआर राव का 24 जुलाई को निधन हो गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व प्रमुख राव ने 85 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मद्रास यूनिवर्सिटी से स्नातक और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाले प्रोफेसर राव ने गुजरात यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी। उसके बाद उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक कहे जाने वाले विक्रम साराभाई के अधीन कॉस्मिक किरण से जुड़े वैज्ञानिक के रूप में करियर की शुरुआत की। इसके अतिरिक्त वे अमेरिका के मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से फ़ैकल्टी मेंबर और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से बतौर सहायक प्रोफेसर भी जुड़े थे। 1984 से 1994 तक उन्होंने इसरो की कमान संभाली। इसरो के चेयरमैन का पद संभालने के बाद उन्होंने रॉकेट तकनीक के क्षेत्र में विकास को गति दी। उन्हीं के नेतृत्व में एएसएलवी और पीएसएलवी का सफल प्रक्षेपण संभव हुआ। उन्होंने जीएसएलवी और क्रायोजेनिक तकनीक के विकास पर भी बल दिया।

उपलब्धियां

1. 1975 में आर्यभट्ट सेटेलाइट की लॉन्चिंग से लेकर चंद्रयान और मंगलयान तक भारत के लगभग सभी बड़े अभियानों में राव की अहम भूमिका रही थी।
2. प्रस्तावित आदित्य सौर मिशन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। भास्कर, एप्पल, रोहिणी, इनसैट-1, इनसैट-2, आइआरएस-1ए, आइआरएस-1बी और इस श्रेणी के अन्य उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण प्रोफेसर राव की उपलब्धियों में शामिल रहा।
3. भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रिम योगदान के लिए प्रोफेसर राव को 1976 में पद्म भूषण और 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अमेरिका के सम्मानित सेटेलाइट हॉल ऑफ फेम में जगह पाने वाले राव पहले भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे।

स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य

मद्रास उच्च न्यायालय ने समूचे तमिलनाडु के स्कूलों में हफ्ते में कम से कम दो बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना आज अनिवार्य कर दिया। न्यायमूर्ति एम वी मुरलीधरन ने आदेश में कहा कि राज्य के निजी और सरकारी स्कूल सुनिश्चित करें कि उनके छात्र कम से कम हफ्ते में दो बार, बेहतर हो, सोमवार और शुक्रवार को राष्ट्रीय गीत गाएं। न्यायाधीश ने कहा कि गीत को महीने में कम से कम एक बार अन्य सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में भी बजाया जा सकता है। उन्होंने कहा, अगर लोगों को बंगाली या संस्कृत में गीत गाने में दिक्कत होती है तो तमिल में इसका अनुवाद करने के लिए कदम उठाए जा सकें।

क्या है

1. बहरहाल, न्यायाधीश ने कहा कि किसी कार्यक्रम में अगर किसी व्यक्ति या संगठन को गीत गाने या बजाने में दिक्कत है तो उन्हें इसे गाने के लिए बाध्य या मजबूर नहीं किया जाएगा बशर्ते उनके पास ऐसा करने का वैध कारण हो।
2. इस देश के युवा कल का भविष्य हैं और अदालत उम्मीद करती है और विश्वास करती है कि इस आदेश को सही भावना में लिया जाएगा और इस महान देश के नागरिक इसे शब्दशः लागू भी करेंगे।
3. मामला के वीरमाणि की याचिका से संबंधित है जो बीटी सहायक पद की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहे थे क्योंकि उन्होंने जवाब दिया था कि गीत बंगाली में लिखा गया है।
4. बोर्ड की ओर से वस्तुनिष्ठ सवाल के बंगाली जवाब को गलत करने के बाद उन्होंने अदालत का रुख किया था। उन्हें 89 अंक दिए गए थे जबकि नियुक्ति के वास्ते योग्य होने के लिए न्यूनतम 90 अंक चाहिए थे।
5. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि गलत मूल्यांकन के कारण वह एक अंक से पद पर भर्ती होने से चूक गया और उसने मांग की कि वंदे मातरम के सवाल के जवाब को सही मानकर उसे एक अंक दिया जाए।

6. यह मामला सात जुलाई को पहली बार सुनवाई के लिए आया तो याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत बंगाली और संस्कृत में लिखा है।
7. दूसरी ओर, सरकारी वकील ने दलील दी कि इसे सिर्फ संस्कृत में लिखा गया था और बाद में बंगाली में इसका अनुवाद किया गया था।
8. याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उसमें बंगाली का जिक्र पहली भाषा के तौर पर है जिसमें राष्ट्रीय गीत लिखा गया था।
9. इसके बाद, न्यायाधीश ने महाधिवक्ता को उनके सामने पेश होकर अदालत को सही उत्तर बताने का निर्देश दिया, ताकि बीएड स्नातक की ओर से उठाए गए गीत के भाषाई मूल के विवाद का निबटारा किया जा सके।
10. इसके बाद, 13 जुलाई को जब मामले पर सुनवाई हुई तो तमिलनाडु के महाधिवक्ता आर मुथुकुमारस्वामी ने अदालत को सूचित किया कि **राष्ट्रीय गीत संस्कृत मूल का है लेकिन वास्तविक तौर पर चटर्जी ने बंगाली में लिखा था।**

तंबाकू नियंत्रण में भारत वर्ल्ड लीडर

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने तंबाकू नियंत्रण में भारत को विश्व प्रणेता (वर्ल्ड लीडर) बताया है। गत 19 जुलाई को न्यूयॉर्क में डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी 'ग्लोबल टोबैको एपिडिमिक-2017' की रिपोर्ट में तंबाकू नियंत्रण के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की गई है।

क्या है

1. उल्लेखनीय है कि हाल ही में जारी ग्लोबल एडवर्ट्स टोबैको सर्वे (गेट्स-2)-2017 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गत सात वर्षों में तंबाकू उपभोक्ताओं की संख्या 34.6 से घटकर 28.6 फीसद हो गई है। यानी छह फीसद तंबाकू उपभोक्ता कम हुए हैं।
2. इसी रिपोर्ट के आधार पर डब्ल्यूएचओ ने 'ग्लोबल टोबैको एपिडिमिक-2017' की रिपोर्ट में भारत को विश्व प्रणेता माना है। आंकड़े बताते हैं कि भारत सरकार द्वारा जागरूकता बढ़ाने, तंबाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार पर रोक लगाने के बाद सात साल में 81 लाख उपभोक्ताओं ने तंबाकू से तौबा कर लिया।
3. प्रचार-प्रसार पर रोक लगाने के प्रयासों का नतीजा है कि भारत को विश्व प्रणेता का दर्जा मिला है। तंबाकू नियंत्रण में सख्ती बरतने के मामले में दुनिया के टॉप 100 शहरों की सूची में भी भारत के कई शहर शामिल हैं।
4. भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर तंबाकू के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम चलाया। साथ ही तंबाकू छोड़ने वाले लोगों के लिए वर्ष 2016 में टोल फ्री नंबर जारी किया।
5. डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में होने वाली हर 10 मौत में से एक मौत तंबाकू के कारण ही होती है। करीब 70 लाख लोग दुनियाभर में प्रतिवर्ष तंबाकू के कारण ही मरते हैं।
6. भारत के अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश व फिलीपींस ने भी तंबाकू नियंत्रण में लोहा मनवाया है।

ऐसे मिली कामयाबी

1. तंबाकू के इस्तेमाल व रक्षात्मक नियमों की निगरानी रखकर
2. धूमपान से लोगों को बचाकर
3. तंबाकू छोड़ने के लिए सहायता देकर
4. तंबाकू से खतरों के प्रति लोगों को आगाह करके
5. तंबाकू उत्पादों के प्रचार, प्रमोशन व स्पॉन्सरशिप पर प्रतिबंध लगाकर
6. तंबाकू उत्पादों पर टैक्स की दर बढ़ाकर

फिर बुकर पुरस्कार की होड़ में अरुंधति रॉय

लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति रॉय 20 साल बाद फिर मैन बुकर पुरस्कार की होड़ में शामिल हुई हैं। उपन्यास 'द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस' के लिए उन्हें इस साल की पहली सूची में शामिल किया गया है। 1997 में उपन्यास 'गॉड ऑफ स्माल थिंग्स' के लिए रॉय को बुकर पुरस्कार से नवाजा गया था।

क्या है

1. 'द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस' उपन्यास एक भारतीय ट्रांसजेंडर महिला के जीवन पर आधारित है।
2. जजों ने इसे एक समृद्ध और संवेदनशील उपन्यास बताया है। इस साल सूची में जगह बनाने वाली रॉय इकलौती ऐसी लेखिका है, जिन्हें पहले भी इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है।
3. उनके अतिरिक्त सूची में चार ऐसे लेखक शामिल हैं, जो पहले भी पुरस्कार के लिए नामित हो चुके हैं, लेकिन जीत नहीं सके। इनमें लेखक अली स्मिथ को 'ऑटम' के लिए सूची में शामिल किया गया है। वहीं जेडी स्मिथ को उनकी कहानी 'स्विंग टाइम', सेबेस्टियन बेरी को 'डेज विथाउट एंड' और मोहसिन हामिद को 'एक्जिट वेस्ट' के लिए सूची में शामिल किया गया है।
4. सूची में भारत की अरुंधति के अलावा चार ब्रिटिश, चार अमेरिकी, दो आइरिश और दो ब्रिटिश पाकिस्तानी लेखकों को शामिल किया गया है।
5. 13 लोगों की इस पहली सूची में से अगले चरण में छह नाम चुने जाएंगे। इन छह नामों की घोषणा 13 सितंबर को होगी। बुकर पुरस्कार विजेता के नाम का एलान 17 अक्टूबर को किया जाएगा। पिछले साल अमेरिकी लेखक पॉल बेटी को द सेलआउट के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला था।
6. मैन बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन जिसे लघु रूप में मैन बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार भी कहा जाता है। कॉमनवैलथ या आयरलैंड के नागरिक द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए हर वर्ष दिया जाता है।

देश के 14वें राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद

रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, इस दौरान संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। चीफ जस्टिस ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इससे पहले शपथ ग्रहण से पहले कोविंद ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी इस दौरान उनकी पत्नी भी मौजूद थीं। नव-निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेने के बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद राष्ट्रपति ने अपना भाषण दिया।

क्या है

1. 20 जुलाई को आए नतीजों में रामनाथ कोविंद को कुल 702044 मिले हैं जबकि मीरा कुमार को 367314 वोट मिले थे। जीत के बाद कोविंद ने जीत के बाद कहा कि सभी लोगों ने मुझपर जो विश्वास जताया है, उसके लिए सभी का आभारी हूँ।
2. भारत के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 71 वर्ष के हैं और कानपुर के रहने वाले हैं। इनका जन्म कानपुर के परौख गांव में हुआ था। कोविंद 1999-2002 के बीच भाजपा के दलित फ्रंट के सचिव रहे।
3. इन्होंने कानून और कॉमर्स विषय में कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक किया है।
4. इसके बाद वो आईएएस की तैयारी करने दिल्ली आ गए। तीसरे प्रयास में उन्होंने यह परीक्षा पास कर ली लेकिन अपने पसंद का विभाग न मिलने की वजह से उन्होंने इसे ठुकरा दिया और एक वकील के रूप में कार्य करने लगे।
5. 1971 में रामनाथ कोविंद को दिल्ली बार कौंसिल का वकील नियुक्त किया गया। वे 1977 से 1979 के बीच दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील रहे। वहीं 1980-1993 के बीच वह सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के सलाहकार रहे। कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में 16 साल तक कार्य किया।
6. राष्ट्रपति कोविंद उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के एमपी भी रहे। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया।
7. 1977 में भाजपा में शामिल होने से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में भी कार्य किया था।

8. रामनाथ कोविंद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, डॉ. भीम राव आम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ और आईआईएम कोलकाता के बोर्ड सदस्य भी रह चुके हैं।
9. 8 अगस्त 2015 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रामनाथ कोविंद को बिहार के राज्यपाल की शपथ दिलाई।
10. रामनाथ कोविंद ने परौख स्थित अपना पुश्तैनी घर गांव वालों को दान कर दिया।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय स्थापना दिवस

प्रत्येक वर्ष 27 जुलाई को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय स्थापना दिवस मनाया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मानसून पूर्वानुमान तथा अन्य मौसम/जलवायु मानकों, समुद्री स्थिति, भूकंप, सुनामी तथा पृथ्वी प्रणाली से संबंधित अन्य घटनाओं के बारे में श्रेष्ठ संभावित सेवाएं प्रदान करता है। मंत्रालय समुद्री संसाधनों (जीवित और अजीवित) की खोज और दोहन के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी कार्य करता है तथा अंटार्कटिक / आर्कटिक / हिमालय तथा दक्षिणी समुद्री अनुसंधान के लिए मॉडल भूमिका अदा करता है।

क्या है

1. इस वर्ष भी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 27 जुलाई, 2017 को स्थापना दिवस मनाया गया है। अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. माइकल मैकफेडेन स्थापना दिवस व्याख्यान दिए।
2. पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध वैज्ञानिकों / इंजीनियरों के प्रमुख योगदानों को उचित मान्यता और मंच देने तथा पृथ्वी प्रणाली विज्ञान की मुख्य धारा में आने के लिए युवा अनुसंधानकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए ईएसएसओ ने लाइफ टाईम एक्सेलेंस अवार्ड और राष्ट्रीय पृथ्वी प्रणाली विज्ञान पुरस्कार गठित किया है।
3. इस वर्ष का लाइफ टाईम एक्सेलेंस अवार्ड प्रो. के गोपालन को स्थानिक भूविज्ञान क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। समुद्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वायुमण्डलीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा भूविज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार क्रमशः प्रो. पी एन विनयचन्द्रन, डॉ. के कृष्णमूर्ति तथा प्रो. के एस कृष्णा को दिए गए।
4. पृथ्वी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय कार्य के लिए युवा अनुसंधान पुरस्कार डॉ. धन्य सी टी तथा डॉ. विक्रम विशाल को दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वैज्ञानिकों को मेधा प्रमाण पत्र दिए गए।

दुनिया का सबसे लंबा हैंगिंग पेडेस्ट्रियन ब्रिज

जर्मेट के स्विस टाउन में दुनिया का सबसे लंबा हैंगिंग पेडेस्ट्रियन ब्रिज खुला है। यह पुल सिर्फ लोगों के चलने के लिए बनाया गया है। इसे दुनिया में सबसे लंबा पुल माना जा रहा है। यह पुल 500 मीटर लंबा है। इस पुल का नाम 'यूरोप ब्रिज' रखा गया है। यह ग्रैबेनगूफर रैवीन से 85 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।

क्या है

1. द जर्मेट टूरिस्ट बोएद का कहना है कि भले ही दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित पुल ऑस्ट्रिया में हो लेकिन यूरोप ब्रिज सबसे लंबा है। इससे पहले यहां एक पुल था जो पहाड़ से पत्थरों के गिरने की वजह से टूट गया था।
2. इस नए पुल की खासियत यह है कि इसमें करीब 80 टन के केबल लगे हैं जो इसको लोगों के चलते समय झूलने से रोकते हैं। यह पुल मुख्य रूप से हार्डकर्स के लिए बनाया गया है।
3. यह जर्मेट से दक्षिणी स्विट्जलैंड जाते समय रास्ते में पड़ता है। यहां से मैटरहॉर्न पहाड़ियों का एक बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई देता है।

भाभा को ले जा रहे जहाज का मलबा फ्रांस में मिला

फ्रांस के आल्प्स की पहाड़ियों पर मॉन्ट ब्लां में दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा और कुछ बॉडी पार्ट मिले हैं। आशंका वक्त की जा रही है कि ये 1966 में क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान के अवशेष हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा

आयोग के अध्यक्ष और भारत के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की मौत भी एयर इंडिया की इसी विमान दुर्घटना में हुई थी। **पर्वतारोही डेनियर रॉश को विमान दुर्घटनाओं के बाद उनके अवशेषों को तलाशना पसंद है।**

क्या है

1. डेनियल कई वर्षों से विमान हादसों में जान गंवाने वाले लोगों के अवशेषों की बासोन ग्लेशियर में तालाश कर रहे थे। इस मिशन में गुरुवार को उनके हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। उन्हें एक दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा और कुछ बॉडी पार्ट्स मिले हैं।
2. डेनियर ने बताया, मुझे इससे पहले कभी कोई महत्वपूर्ण मानव अवशेष नहीं मिला था। बताया जा रहा है कि इस बार डेनियर को हाथ और पैर का ऊपरी भाग मिला है।
3. मॉन्ट ब्लां में अब तक दो बड़ी विमान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। **मुंबई से न्यू यॉर्क जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 707 जनवरी 1966 में मॉन्ट ब्लां के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।**
4. इस दौरान विमान में सवार सभी 117 लोगों की मौत हो गई थी। इसी विमान में होमी जहांगीर भाभा भी सवार थे। भाभा एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वियना जा रहे थे। इस विमान दुर्घटना का रहस्य आज तक नहीं खुल पाया है।
5. इसी जगह साल 1950 में एयर इंडिया के एक अन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 48 लोगों की मौत हो गई थी। रॉश ने कहा है कि जो अवशेष मिले हैं वे 1966 में दुर्घटना का शिकार हुई बोइंग 707 उड़ान की किसी महिला यात्री के प्रतीत होते हैं। उन्हें उस विमान के 4 जेट इंजनों में से एक इंजन भी मिला है।

भारत ने उत्तर कोरिया को किया बैन

अमेरिका और चीन जहां उत्तर कोरिया के मुद्दे पर नये सिरे से बातचीत कर रहे हैं कि कैसे प्योंगयांग की हरकतों पर लगाम लगाई जाए। वहीं भारत जैसे देशों ने भी उत्तर कोरिया से संबंध सीमित करने शुरू कर दिए हैं। पिछले साल के मुकाबले भारत और उत्तर कोरिया के व्यापार में 30 प्रतिशत की कमी देखने को मिली है। उत्तर कोरिया के सभी संपर्कों को कैसे काटा जा सकता है, इस पर चर्चा के लिए विदेश विभाग के एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने इस हफ्ते नई दिल्ली का दौरा किया। भारत को सुझाव में प्योंगयांग के साथ अपने राजनयिक संबंध को सीमित करने को कहा गया है। दरअसल, उत्तर कोरिया के तानाशाह कीम जोंग अपने आक्रामक रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं।

क्या है

1. उत्तर कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दुनिया में एक बार फिर से हड़कंप मचा दिया है। मिसाइल लॉन्च के बाद कीम जोंग उन ने कहा है कि उनकी यह नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज पूरे अमेरिका तक है। इसके अलावा देश के कई अन्य देश भी इस मिसाइल की जद में हैं।
2. अमेरिका ने अब उत्तर कोरिया की घेराबंदी शुरू कर दी है। सूत्रों की मानें तो अमेरिका चाहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर कोरियाई गतिविधि को रोकने में भारत मदद करे।
3. 2016 में उत्तर कोरिया में भारत का निर्यात 110 मिलियन डॉलर था, जिसमें इस साल काफी कमी आई है। अधिकारियों के मुताबिक, द्विपक्षीय व्यापार में 30 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। चीन, उत्तर कोरिया का सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार है। इस साल चीन उत्तर कोरिया में चीन का निर्यात काफी बढ़ गया है।
4. भारतीय अधिकारी का कहना है कि भारत भले ही नॉर्थ कोरिया का तीसरा बड़ा निर्यात देश है, लेकिन इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा, 'जब किसी देश का 95 प्रतिशत व्यापार एक ही देश (चीन) से हो, तो दूसरे देशों के प्रतिबंध लगाने से कोई खास फर्क पढ़ने वाला नहीं है।' बता दें कि अमेरिका अब तक चीन को नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए राजी करने में कामयाब नहीं हो पाया है।